www.anivaryaprashna.in // Fallow

हिन्दी मासिक

# अनिवार्य प्रश्न

चन्दौली–वाराणसी से सम्पूर्ण भारत के लिए प्रकाशित व प्रसारित

RNI UPHIN/2019/80493 वर्ष 04, अंक 02, फरवरी, 2022, पृष्ठः 8, : सहयोग मूल्य : 11 रुपए

अगर पढ़िए तो सिर्फ सच पढ़िए!

आखिरकार पकड़ना ही... 2 | क्या दुष्कर्म होते ही रहेंगे? 5 | गोकशी बदस्तूर जारी 7

# घाव घाव रह गये, आह आह रह गयी रात को सबेर की अटूट चाह रह गयी

**राजतंत्रों से लेकर प्रजातंत्र तक सत्ता, शक्ति व कुर्सी के लिए संघर्ष होता रहा हैं। इस संघर्ष में जनता के सारे मूल मुद्दे अब तक सुलझ पाए हैं कि नहीं? हमारी टीम इसी की समीक्षा कर रही हैं। हम लोगों को यह बताना चाह रहे हैं कि सरकारों, विभिन्न नेताओं और विभिन्न पार्टियों के गढ़े प्रशासनिक ढाचों से आम आदमी के कौन से मूलभूत मुद्दे सुलझाने बाकी रह गए हैं...**

**अनिवार्य प्रश्न। डेस्क**

हर हाल में सरकारों ने रोजगार और समाज को सुंदर बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन परिणाम निराशाजनक ही रहे। आबादी अपेक्षा से अधिक बढ़ गई और सच्चाई में भुखमरी जितनी थी उससे ज्यादा हो गई। राजतंत्र में भी कुपोषण था और प्रजातंत्र में भी कुपोषित बच्चे मिलते हैं। अगर उस समय उचित चिकित्सा व्यवस्था की समस्या थी तो प्रजातंत्र के 70 साल व्यतीत हो जाने के बाद भी चिकित्सा की समस्या बनी हुई है।

रोजगार की समस्या भी वैसे ही मुंह बाए खड़ी है और शिक्षा तो पूरी तरह व्यापारियों के हाथ में चली गई। तब शिक्षा आसान थी अब शिक्षा महंगी है। कुल मिलाकर आम आदमी के हाथ कुछ दुश्वारियां और कुछ टैक्स के सिवाय कुछ नहीं आया। कुछ सड़कों, बिजली व पानी के लिए उसे भारी बिल भरना है। आज भी रोजी–रोटी की समस्या वैसी ही है। जीवन की संवेदना के दर्द वैसे ही हैं। साथ ही अलग–अलग बिंदुओं पर कर भरता भारतीय समाज विकास के इंतजार में बैठा तो है पर सही मायने में उसे अभी पूरी तरह शिक्षा व चिकित्सा, रोटी और कपड़े की पूरी आश्वस्थता नहीं मिल पाई है। भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से के लिए आज भी रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा व मकान बड़ी समस्या व बड़े सपने से कम नहीं हैं।

आज भी ऐसे बहुत से घर हैं जिनके पास ठीक से पूरी छत नहीं है। तब से आज तक यह चिंता उतनी ही गम्भीर बनी हुई है। पुलों और सड़कों के किनारे झुग्गियों में तब बंजारे रहते रहे होंगे पर अब बंजारे नहीं हैं, तो ये कौन हैं? इस पर काम कभी क्यों नहीं हुआ यह आज भी सबसे बड़ा प्रश्न है। आज भी हर शहर व गांव में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको ना ही छत मिल पायी ना ही पूरा आवास। कुछ को मिले तो आधे अधूरे मिले। और बाकी भ्रष्टाचार की बलि चल गए। आम आदमी यह कतई नहीं जानता कि दस्तावेजों और सरकारों में क्या हो रहा है, और क्या अच्छा है क्या बुरा है। रोजी–रोटी और विकास के नाम पर 70 साल के मूल अधिकार प्राप्त प्रजातांत्रिक युग में लाखों रुपए टैक्स देने के बाद भी उसे राहत क्यों नहीं मिली, रोजी के साथ उसे छत क्यों नहीं मिली?

रोजगार के गारंटी कानून लाने के बाद भी अनेक परिवार ऐसे हैं जिनका पेट भरना मुहाल है। बात सिर्फ ग्रामांचल के परिवारों की ही नहीं है शहरी जीवन में भी ऐसे परिवार हैं जिनके पास सुबह और शाम के खाने का उत्तम प्रबंध नहीं है। सरकारें रोजगार के सृजन, उसकी संभावना के निर्माण एवं रोटी के समुचित और निश्चित प्रबंध से स्वयं को बचाती रही हैं। भारत में सरकार का यह भी एक दुःखद चेहरा है कि लगभग एक सदी होने वाला है पर प्रत्येक नागरिक के पास जीविका का पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध नहीं है। हाथ गाड़ी खींचकर भी व्यक्ति के पास जब रोटी घट जाती है तो राष्ट्रीय चिंतकों की आंखों से खून क्यों नहीं निकल आता? मनीषी क्या कर रहे हैं? और अब तक यह छत–रोटी, पढ़ाई–दवाई की समस्या हल क्यों नहीं हुई? यही इस देश में सदियों से अनिवार्य प्रश्न रहा है। आइए बिन्दुवार जानें–

### उचित शिक्षा व्यवस्था का अभाव–

हांलाकि शिक्षा व्यवस्था के प्रति सरकारों ने विशेष ध्यान तो दिया है पर आज भी एक वर्ग ऐसा है जिस तक अच्छी शिक्षा पहुंचाई नहीं जा पा रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि शिक्षा को कार्पोरेटर के हाथ में दे दिया गया है। रोजगारपरक शिक्षा अब सरकार अपने स्वयं संचालित करने में कम दिलचस्पी ले रही है। चिकित्सा और व्यापारिक सेवाओं में कौशल विकास के लिए लाई गई विशेष योग्यताओं वाली शिक्षा जैसे डॉक्टरी व इंजीनियरिंग को इतना महंगा कर दिया गया कि अब आम परिवारों के बच्चे उसे अर्जित नहीं कर सकते। गरीब परिवारों के बच्चे कथित रूप से मुक्त चलाई जाने वाली आठवीं तक की शिक्षा प्राप्त तो कर सकते हैं लेकिन इसके आगे का रास्ता उनके लिए महंगा और दुरुह है।

आज के समय में स्नातक व परास्नातक की शिक्षा भी इतनी महंगी हो गई है कि उसे भी आम आदमी के लिए बहुत सुलभ व सरल नहीं कहा जा सकता। कहने के लिए सरकारों ने छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है लेकिन कितनों को मिलती है आम आदमी खूब जानता है।

### चिकित्सा व्यवस्था की व्यापक कमी–

सरकारी अस्पतालों के रवैए को बताते समय उसकी संवेदनहीनता प्रमुख बात बन कर सामने आती है। दूसरी प्रमुख बात जो आम लोगों को जीनी पड़ती है वह उसमें सुविधाओं व उपयुक्त व्यवस्थाओं का अभाव। इन दोनों कारणों से सरकारी संस्थानों व चिकित्सा केंद्रों में आकस्मिक चिकित्सा प्रणाली विश्वसनीय नहीं रही है।

आम आदमी अपने स्वास्थ्य के बड़े संकट को लेकर प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाओं के संचालकों के हाथ में फंस जाता है और उसे इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। सरकार आज तक अपनी चिकित्सा सेवा व उसकी पर्याप्तता को लेकर सवालों के घेरे में रही है। 70 से अधिक वर्षों से स्वतंत्र भारत की विकास यात्रा को देखें तो भी चिकित्सा अभी वहीं खड़ी है जहां इसे तब देखा व समझा जाता था। आबादी और आवश्यकता के अनुसार चिकित्सा व्यवस्था अल्प साबित हुई है। अभी भी बेहद उत्तम चिकित्सकीय समाधान और बेहतर आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था के इंतजार में समाज बैठा हुआ है।

### जनसंख्या नियंत्रण–

जाने किस डर से आज तक सरकारों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कठोर कानून लाने से गुरेज किया है। हालांकि देश की तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या भले विश्व को व्यापक बाजार व बाजारी संस्कृति के लिए आकर्षित की हो पर इस देश की दुर्दशा इसकी जनसंख्या के बढ़ते घनत्व से ही हो रही है। आबादी का 70 साल में ही 3 गुना हो जाना यह बताता है कि हम विकास नहीं पतन कर रहे हैं। सरकार में शामिल व सरकार चला रहे उन लोगों के लिए यह बहुत बड़ा प्रश्न है।

उन्हें साहस करके अपनी बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए आंशिक संदेशप्रद कानून नहीं बल्कि कठोर कानून के निर्माण की बेहद जरूरत है। बीजेपी सरकार ने इस में कमोबेश कदम उठाया तो जरूर है पर अभी तक सभी सरकारों में उस शिद्दत की कमी रही है जिस शिद्दत के बल पर सामाजिक समर्पण से जनसंख्या नियंत्रण हेतु कठोर कानून लाया जा सके।

इस देश की संपूर्ण समस्याओं को निपटाने में जनसंख्या नियंत्रण कानून सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अभी तक की सरकारों ने इस पर विशेष रुचि व हिम्मत नहीं दिखाई है।

### जातिगत आरक्षण की व्यवस्था–

लंबे समय से आरक्षण की व्यवस्था सवाल के घेरे में रही है जो कि जातिवादी आधार पर है। जातिवाद का विरोध करने वाले और धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करने वाले देश व समाज के लिए जाति आरक्षण की व्यवस्था भी एक सामाजिक कोढ़ है। आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से विकसित करने के उद्देश्य से चालू की गई जातिगत आरक्षण की व्यवस्था में वर्तमान सरकार ने थोड़ा सा बदलाव तो किया है लेकिन अभी इसे सही तौर पर व्यापक सुधार का इंतजार है। सही अर्थों में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर ही समाज का सही भला किया जा सकता है। अनेक समाज चिंतकों का कहना है कि जिसको आवश्यकता है उसको ही संरक्षण मिले, समर्थ को संरक्षण मिलना या संरक्षण की पुनरावृत्ति होना भी जाति आरक्षण प्रणाली की एक बड़ी खामी है।

### सरकारी सेवकों की तनख्वाह में कमी–

सरकारी नौकरशाहों के सांगठनिक आंदोलनों के कारण पीछे की कई सरकारों ने उनकी तनख्वाह में अप्रत्याशित व अपेक्षा से अधिक वृद्धि कर दिया। आज कई सारे सरकारी पदों और नौकरियों पर इतनी तनख्वाह जारी की जा रही है कि सरकार के राजस्व का बड़ा भाग उसी पर खर्च हो जाता है। आजादी के समय से अब तक निजी सेक्टर में की गई तनख्वाह वृद्धि के अनुपात में सरकारी सेवाओं में तनख्वाह की व्यापक और असंतुलित की वृद्धि की गई है। जिससे निजी सेक्टर में सेवा देने वाला एक बड़ा समूह भारत का तुलनात्मक व आर्थिक रूप से पिछड़ गया है। ठीक वैसे जैसे राजतंत्र में मंत्री आगे निकल जाते थे और आम आदमी गरीब बनकर वहीं रह जाता था। नीति आयोग ने पिछले दिनों कुछ सुधार किए हैं जिसमें शिक्षकों की तनख्वाह की अधिकतम सीमा तय की गई है लेकिन अभी अन्य सरकारी सेवाओं में उच्चतम तनख्वाह को निर्धारित नहीं किया गया है।

आम आदमी चाह रहा है कि अब सरकारी सेवाओं में आम आदमी से अर्जित कर का बेशुमार धन व्यय न किया जाए।

### वर्तमान समय में कमजोर हुई आरटीआई

यह ऐसा कानून है जिससे सरकारी विभाग में किए जाने वाले गलत कार्यों व की गई खराब सेवाओं के बारे में आदमी जानकारी व गुणवत्ता मानक जान सकता है और अपने रुके हुए कार्यों के संबंध में रुकने के कारण की पड़ताल कर सकता है। लेकिन आरटीआई कानून को इस समय शिथिल हुआ माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आयोग में भी जिनकी कई अपीलें सुनवाई के लिए की गई हैं उनमें सिर्फ 2 से 3 अपीलों पर सुनवाई चल रही है। बाकी सभी पेंडिंग हैं। आरोप लगता रहा है कि जाने किसकी मंशा रही है कि आईटीआई का प्रयोग करने वाले बहुतायत लोग नकारात्मक खेमे के हैं लेकिन ऐसा नहीं है। सभी तरह के विचारधारा वाले लोग भी आरटीआई का प्रयोग करते हैं। सभी लोग आयोग में काम के अधिकता के कारण भी होने वाले विलम्ब को भी वर्तमान व्यवस्था की सुस्ती समझ रहे हैं।

### आस अधूरी है अभी

चाणक्य ने कहा था कि राज्यों को कर भोजन में नमक के समान लगाना चाहिए। जो जिंदगी को स्वादिष्ट बनाएं न कि दुखदाई। स्वतंत्र भारत सरकारों ने छोटे–छोटे बिंदुओं को खोज–खोज कर इतने टैक्स लगा दिए कि आम आदमी करों के बोझ से दब गया है। कितनी भी मेहनत कर ले पर उसे रुपये कम पड़ते हैं और उसे फिर काम में जूझना पड़ता है। उसके पास अपनी आवश्यकता में ही हमेशा कमी जान पड़ती है। इसीलिए वह हमेशा कमाने में लगा रहता है। उसके पास अब रचनात्मक कार्य व पारंपरिक मूल्यों के निर्वाह के साथ रिश्तों के लिए समय नहीं बचा। राज्य को चाहिए कि गैरजरूरी कर धीरे–धीरे कम करे व विकास की योजनाओं को आडम्बर हटाकर सही दिशा दे। आम आदमी आज केंद्र के साथ–साथ अपनी नगर निकायों को भी अनेक टैस भर रहा है। कर इतने हो गए हैं कि आज आदमी कर भरे की जिये इस उधेड़बुन में उलझा हुआ है। सरकारी सेवकों पर कृपा लुटाने वाली सरकारें आम आदमी के लिए कर निर्धारण में कृपालु नहीं रही हैं। अंत में कवि 'कुंठित' यह कविता बेहद प्रासंगिक है–

**घाव घाव रह गये, आह आह रह गयी। रात को सबेर की अटूट चाह रह गयी।**
**प्रात पा सका न तम, भोर पा सके न हम, रह गया तिमिर गहन, निशा अथाह रह गयी।**

## बड़ा सच

### पचीसों साल से बनारस जिले में टिके हैं क्लर्क

अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद। वाराणसी। देश के प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भ्रष्टाचार व रसूख पसंद लोगों का बोलबाला खूब है। सूचना उपनिदेशक कार्यालय सहित जिले के विभागों के दफ्तरों में 25 साल से अधिक से क्लर्क बैठे हैं। और अपने काम को अच्छे से भ्रष्टाचार व दबंगता पूर्वक अंजाम दे रहे हैं। एक आरटीआई में हुए खुलासे में यह बात सामने आई है कि जिले में ऐसे कई कर्मचारी व अधिकारी हो सकते हैं जो वर्षो से इसी जिले में घूम फिर सेवा दे रहे हैं। और उनका तबादला नहीं किया गया है।

एक आरटीआई कार्यकर्ता ने अनिवार्य प्रश्न को बताया कि सूचना विभाग का एक बाबू अनिल श्रीवास्तव जो पत्रकारिता को भी अपने हिसाब से करवाना चाहता है जिले में लगभग 3 दशक से कार्य कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक वह दंभी है और पत्रकारों को भी अपनी शर्तपर सूचना देता व पास बनाता है।

उक्त लिपिक के खिलाफ हाईकोट में शिकायत वाद दाखिल किया गया है।

वैतनिक पदों पर संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि बनने के लिए संपर्क करें - 9161099088

मर रही है सच्चाई खड़ा करना ही होगा-
अनिवार्य प्रश्न
हर कलम बिकती नहीं।
www.anivaryaprshna.in

## हालात से

# वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट से वापस हो रहीं पूर्व एसएसपी को संबोधित उच्चाधिकारियों की नोटिस

**दण्ड की कार्यवाहियों से बचने का पुलिस ने खोजा नया तरीका**

अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद। वाराणसी। कुछ ही महीने पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बदलकर पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू की गई है। बनारस में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम से आने वाली चिट्ठियां अस्वीकार की जा रही हैं।

यहां तक कि राज्य सूचना व केंद्र सूचना आयोग से भेजी जाने वाली चिट्ठियां भी पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही हैं।

इससे साफ जाहिर है कि पुलिस अपने अतीत से भाग रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस कमिश्नरेट हो जाने के बाद पुलिस अधीक्षक को संबोधित विभिन्न उच्च विभागों से आने वाले समन व नोटिस, पुलिस के खिलाफ की गई शिकायतों के सापेक्ष कार्यवाही के पत्र एवं आयोग में सुनवाई के दौरान जारी होने वाले निर्देश और दंड के पत्र को वाराणसी पुलिस विभाग स्वीकार नहीं कर रहा है और अपने खिलाफ होने वाली कार्यवाही से बचा रहा है।

वाराणसी के एक अन्य आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि उसके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई एक शिकायत पर कार्यवाही नहीं की गई। जिसपर उसने सूचना मांगा। न तो शिकायत की सुनवाई हुई और ना ही सूचना दी गई। फिर आयोग में अपील के बाद जब आयोग से नाटिस आती है तो वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट से उसे स्वीकार नहीं किया जाता।

उसने बताया कि एक शिकायत के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय वाराणसी के सूचना अधिकारियों द्वारा जवाब नहीं दिया गया था। इसके खिलाफ सुनवाई आयोग में चल रही है। फिर भी अब–तक जवाब नहीं दिया गया है। आयोग की जब नोटिस आ रही है तो उसे लिया नहीं जा रहा है। आयोग के आयुक्त इस बात से दंग हैं कि पुलिस विभाग में चिट्ठी स्वीकार क्यों नहीं की जा रही। विगत दिनों पुलिस विभाग अपनी गैरजिम्मेदारियों पर अलग – अलग उच्च विभागों से कार्यवाहिओं के लिए जारी हुए आदेश, समन एवं नोटिस को रिशिव नहीं कर रहा है।

# बालू की बोरियों के सहारे वरुणा कॉरीडोर

## लाज बचाने की जद्दोजहद में वीडीए

अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद। वाराणसी। स्थानीय विकास प्राधिकरण के अनुसार वरुणा किनारे ई–रिक्शा कारिडोर का दूसरा चरण का काम पूरा हो चुका है। कारिडोर को ई–रिक्शा कारिडोर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। परियोजना की लागत में करीब पांच लाख की बढ़ोतरी की गई है। अब 110 लाख से अधिक खर्च होने का अनुमान है। लेकिन इसमें अनियमितता की अटकलें लगनी शुरु हो गई हैं।

तीसरे चरण का कार्य भी प्रारंभ होने ही जा रहा है। और पहले व दूसरे फेज को लोकार्पण करने की तैयारी भी हो रही है। कारीडोर के रैंप बन गए हैं ऐसे में बड़े वाहनों को प्रवेश से रोकने के लिए लोहे का हाइट गेज भी विभाग ने लगा दिया है। लेकिन इसके साथ ही कारिडोर का रास्ता क्षतिग्रस्त हो चुका है। सारी इंटरलाकिंग उखड़ गई है और तो और रास्ता नीचे से खोखला हो रहा है। प्रशासन बालू की बोरियां लगाकर खोखला हो रहे रास्ते को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है।

सूचना है कि तीन जगहों पर बनने वाले रैंप की डिजाइन में काफी परिवर्तन किया गया है। इसके बाद नक्खीघाट पर बनने वाला रैंप 10 पिलरों पर निमिर्त कर दिया गया है। इसे पायलिंग पिलर के सहारे तैयार किया गया है। उल्लेखनीय है कि वरुणा के शास्त्रीघाट से शुरू होकर पुराने पुल तक ई–रिक्शा कारिडोर को बनाया जा रहा है। योजना है कि बाद में इसकी कनेक्टिविटी खिड़किया घाट से दी जाएगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण चाह रहा है कि जाम से लोगों को राहत मिले साथ ही साथ एक अलग वैकल्पिक मार्ग भी तैयार हो। इसी के तहत ई–रिक्शा कारिडोर के पहले चरण का काम पूरा होते ही दूसरे चरण के काम की शुरूआत नक्खीघाट से की गई है।

# सभी भवनों का विवरण आनलाइन

## बकाया गृहकर की भी मिलेगी जानकारी

अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद। वाराणसी। नगर निगम, वाराणसी द्वारा नगर के सभी भवनों का विवरण डाटा आनलाइन कर दिया गया है। भवन के विवरण में भवन स्वामी का नाम, मकान नम्बर एवं गृहकर का विवरण उपलब्ध है। अब कोई भी भवन स्वामी अपने भवन का विवरण देख सकता है। सभी नागरिक नगर निगम वाराणसी के वेबसाइट www.nnvns.org.in पर जाकर अपने भवन से जुड़ी सूचना को देख सकते हैं।

प्रायः यह देखा जाता है कि कोई भी भवन स्वामी अपने भवन की खरीद या बिक्री करते समय भवन पर बकाये गृहकर की जानकारी नहीं जान पाता था, जिससे उस भवन का नामातंरण कराते समय बकाया गृहकर जमा न होने के कारण सम्बन्धित नागरिक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब कोई भी भवन स्वामी अपने भवन की खरीद अथवा बिक्री करने के पूर्व नगर निगम वाराणसी की वेबसाइट पर उस भवन के गृहकर बकाया के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है, जिससे क्रेता को नामातंरण कराते समय बकाया गृहकर के सम्बन्ध में उसके उपर अतिरिक्त व्यय भार उत्पन्न नहीं होगा।

इतना ही नहीं इसके अतिरिक्त बैंक लोन, विद्युत कनेक्शन, संचार कनेक्शन इत्यादि जन सुविधाएं लेते समय सम्बन्धित विभागीय संस्थायें वेबसाइट के माध्यम से सत्यापन कर सकती हैं। साथ ही कोई भी भवन स्वामी अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट के माध्यम से आनलाईन जमा कर सकता है।

नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी भवन के नामातंरण करने के पूर्व उस भवन पर यदि गृहकर बकाया है तो बिना गृहकर जमा कराये नामातंरण की कार्यवाही नहीं की जाये। इस हेतु साफ्टवेयर में आवश्यक प्राविधान करने हेतु कम्प्यूटर सेल को निर्देशित कर दिया गया है।

# चित्रकारी से याद की गई राष्ट्रसुता निर्भया

अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद। वाराणसी। गंगा के पावन घाट पर लैंगिक हिंसा के ख़िलाफ़ रंग और कूची का संघर्ष देखने को मिला। गंगा किनारे भदैनी घाट पर फड़ पेंटिंग के माध्यम से निर्भया को याद किया गया। लैंगिक हिंसा भेदभाव उत्पीड़न को रोकने का संदेश देने के वाली चित्रकारी से छात्रों व युवाओं ने संवेदना को झकझोरने की सफल कोशिश की।

आयोजक संगठन 'दख़ल' की ओर से एक कार्यकर्त्री ने बताया कि कार्यक्रम कोई जयंती या पुण्यतिथि का कार्यक्रम नहीं है। ना ही यह कोई औपचारिक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम अपने समाज के क्रूर, हिंसक, दर्द देने वाले और डरावने चेहरे को पहचानने के लिये है। 2012 में इस घटना ने हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया था।

अपने एक दोस्त के साथ बस में सफर कर रही निर्भया के साथ कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ शुरू की। बुरी तरह पीटा गया। सामूहिक बलात्कार किया गया। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान 29 दिसम्बर 2012 को निर्भया की दुःखद मौत हो गई।

इस घटना के बाद समाज मे एक अभूतपूर्व उबाल देखने को मिला। क्या सड़क, क्या संसद, हर जगह लोगों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और ऐसे दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की बात की गई। संसद में सर्वमत से महिलाओं के सुरक्षा के विषय मे और हिंसा उत्पीड़न से संरक्षण के लिए कानून बने। उसी नृशंस घटना को याद करते हुए लैंगिक भेदभाव और हिंसा को दर्शाते हुए हम चित्र और संदेशों के माध्यम से जागरूकता और संवाद बनाने की आज भी कोशिश कर रहे हैं।

गौरतलब है की विगत 15 दिसम्बर को ही राज्यसभा में स्मृति ईरानी जी ने कोविड काल में घरेलू हिंसा के आंकड़े पटल पर रखे और बताया कि इस साल घरेलू हिंसा के मामले 3582 दर्ज हुए हैं।

यह आंकड़े बताते हैं कि लैंगिक हिंसा केवल कानून के कड़े होने या दंड से सीमित होने वाला मामला नहीं है। घर में बहन बेटी माँ तक सुरक्षित नही हैं, ऐसे में ये समाज की एक बीमारी है। कार्यक्रम में बीएचयू व काशी विद्यापीठ से काफी संख्या में छात्र–छात्राएं उपस्थित रहीं। आयोजन में वल्लभाचार्य पांडेय, डॉ इंदु पांडेय, अनुष्का, नीति, विजेता, रोली सिंह रघुवंशी, मैत्री मिश्रा, धनन्जय त्रिपाठी, शिवि, दिवाकर सिंह, ज्योति, सलमान, डॉ प्रियंका, ताहिर, शांतनु सिंह, राज, अभिषेक, रोहन, महेंद्र, मूसा आज़मी, शालिनी, साक्षी, साहिल, डॉ प्रफुल्ल चन्द्र राव भारती, डॉ विकास सिंह आदि लोगों की उपस्थिती रही।

# जागिये वाराणसी के डी.एम. साहब कार्यालय में हो रही लापरवाही ढंक दिया गया CCTV

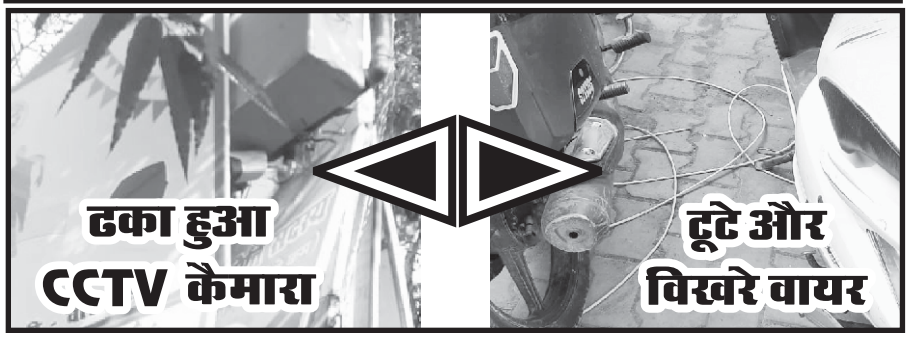


## शिकायतों में लीपापोती, कई दशक से जमें हैं कर्मचारी

अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद। वाराणसी। जिला अधिकारी दफ्तर में जनसुनवाई और जनसुनवायियों के पंजीयन में की जा रही गड़बड़ी की चर्चा तो जिले भर में थी ही अब सीसीटीवी कैमरे के ढक देने की चर्चा व खबर भी जिलेभर में वायरल हो रही है।

वाराणसी के जिला अधिकारी अपनी शिष्टता और अपनी सक्रियता के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन उनके कार्यालय में ही कई सारी अनियमितता प्रकाश में आ रही हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जनपद वाराणसी द्वारा आयोजित स्वास्थ्य से संबंधित एक कार्यक्रम के लिए विधिवत जिला अधिकारी के पद घोषित एक विज्ञापन में उनके कार्यालय के मुख्य द्वार के पास का सीसीटीवी कैमरा ढक दिया गया है। आज जब अपराध अनेकों तरह से और अनेक स्वरूप में विकसित हो रहा है और उसको नियंत्रित करने के लिए सीसीटीवी कैमरा एकमात्र उपाय है, जिलाधिकारी कार्यालय का सीसीटीवी कैमरा कार्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी निभाने को अच्छे से परिभाषित करता है। अभी कुछ दिनों पहले सूचना निदेशक कार्यालय के द्वारा की गई अनियमितता के लिए संकलित की जानकारी में जिले के सूचना विभाग में एक बाबू 25 साल से अधिक समय से एक ही जिला वाराणसी में कार्यरत है। उल्लेखनीय है कि उसके खिलाफ की गई शिकायतों की सुनवाई में खूब लीपापोती हुई है।

लगभग दो साल से चल रही शिकायत के शिलशिले में वर्तमान जिलाधिकारी के स्वयंनाम से कई बार प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। शिकायत कर्ताओं के मुताबिक डीएम साहब जनसुनवायियों की निगरानी नहीं करते। ये भी नहीं देखते होंगे की कार्यालय में किस तरह की गड़बड़ी और लापरवाही चल रही है नहीं तो कैमरा तक ढका नहीं रहता।

हांलाकि ढका हुआ सीसीटीवी कैमरा काफी कुछ बयान कर रहा है। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि बाहर लगे विशाल विज्ञापन बैनर में किसी भी रूप में इतनी जगह नहीं छोड़ी गई है जहां से सीसीटीवी कैमरा की वीडियो सुरक्षा के तहत परिसर सुरक्षित हो।

ऐसे में वाराणसी के डीएम साहब से या निवेदन किया जाता है अगर आप ध्यान नहीं दे रहे और नींद में हैं तो नींद से जागीए और अपने दफ्तर में नजर डालिए जनसुनवायियों की हालत खस्ता है और आप के दफ्तर के बाहर सीसीटीवी कैमरा अंधा हो गया है।

इतना ही नहीं सीसीटीवी कैमरे का तार वाहन पार्किंग के क्षेत्र में ऐसे नीचे झूला और टूटा हुआ है जैसे वह पूरी तरह गैरजरूरी हो।

अगर गैर जरुरी है तो उसे खरीदने में जनता का धन क्यों पानी की तरह बहाया गया। अनिवार्य प्रश्न यह है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? या इस लापरवाही के लिए किस को श्रेय दिया जाएगा?

और कौन गैर जिम्मेंवार आईटी विभाग देख रहा है? वाराणसी के डी.एम., उनकी व उनके ऑफिस की सुरक्षा के लिए यह लापरवाही ठीक नहीं है।

◆◆◆

# गैंगरेप के आरोपी दरोगा को आखिरकार पकड़ना ही पड़ा

प्रासंगिक

## डेढ़ साल पहले का था बनारस का चर्चित मामला

अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद। वाराणसी। 4 बच्चों की मां को नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप करने वाला गैंगरेप का आरोपी और डेढ़ साल से ज्यादा समय से वांछित चल रहा दरोगा उमराव खान को भेलूपुर थाने की पुलिस ने सीतापुर स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से गिरफ्तार कर लिया। उक्त दारोगा उमराव खान पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करने के लिए सीतापुर गया हुआ था। पुलिस टीम ने इसकी पुष्टि कर उसे गिरफ्तार किया। भेलूपुर थाना के अनुसार थाना अंतर्गत बजरडीहा क्षेत्र की एक महिला के साथ 2019 के आखिरी में शर्मनाक गैंगरेप हुआ था। आदमी के रूप में भेड़ियों ने एक 4 बच्चों की मां को नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप किया था। इतना ही नहीं वे उसका वीडियो भी बना लिये थे। उनके साथ का एक युवक उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था।

जब वह वीडियो पीड़िता के पास पहुंचा तो वह 3 फरवरी 2020 को भेलूपुर थाने की पुलिस शिकायत की। गैंगरेप पीड़िता ने पुलिस को बताया कि भेलूपुर थाने की बजरडीहा चौकी पर तैनात दरोगा उमराव खान, बजरडीहा निवासी इब्राहिम, हाजी मैनुद्दीन और एक अन्य साथी ने उसके साथ सामूहिक रेप किया था। पीड़िता ने गैंगरेप का वीडियो वायरल करने का आरोप बजरडीहा के कोल्हुआ निवासी मोहम्मद शाहिद पर लगाया था। पहले ही दरोगा के अतिरिक्त अन्य आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे लेकिन प्रशासनिक कारणों से दरोगा की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी।

पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश ने विगत दिनों इस संबंध में बताया कि आरोपी दरोगा मुकदमे में पहले से वांछित था। भेलूपुर थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। मुकदमा चाहे पुलिसकर्मी पर हो या आम आदमी के खिलाफ हो, हमारा भारतीय कानून सभी के लिए एक समान है।

उल्लेखनीय है कि उमराव खान 30 अक्टूबर 2017 को एक मुकदमे की पैरवी में वाराणसी के कचहरी में आया था। उस समय एक विवाद को लेकर अधिवक्ता दरोगा से भिड़ गए थे। बाद में वकीलों ने दरोगा उमराव की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। तब किसी तरह से छुप कर वह अपनी जान बचा पाया था।

# ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में पिसे किसान

## दशकों के सवाल का जवाब भ्रष्टाचार

अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद। चंदौली। उपज खरीद के मामले में चंदौली प्रशासन की अनियमितता से वहाँ का किसान हमेशा से समस्याओं में गिरा रहा है। यहां के किसान अपने उपज बिक्री को लेकर हमेशा चिंतित रहे हैं। विगत दिनों चंदौली भर से प्राप्त सूचनाओं के मुताबिक किसानों को अपनी उपज को सरकारी खरीद केंद्रों पर बेचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले ऑनलाइन पंजीयन कराने की प्रणाली के तहत लेखपालों की मान्यता व उनसे संस्तुति लेने में काफी जद्दोजहद व परेशानी का सामना किसानों ने किया। इसके बाद फिर पंजीयन ऑफलाइन कर दिया गया। फिर ऑनलाइन कूपन जनरेट किया जाने लगा। जिसमें 10 मिनट के समय में ही किसानों को अपने कूपन जनरेट करने के लिए तत्पर रहना होता था। ऐसे में स्थानीय किसानों को बहुत दिक्कतें हुई।

कई किसान संगठनों का कहना है कि जितने क्वींटल का कूपन जनरेट होता था उससे आधे से भी कम की खरीद की जा रही थी। ऊपर से अधिकारियों का भ्रष्टाचार अपनी जगह कायम था। कई बार तो किसान संगठनों ने विरोध भी किया इसके बाद कुछ एक लोगों का बिना

भ्रष्टाचार के खरीद तो हो सकी लेकिन फिर एक–दो दिन बाद वही क्रम चालू हो गया।

किसान संगठनों से जुड़े कई किसानों का वर्षों से आरोप रहा है कि खरीद प्रणाली में दशकों से व्याप्त भ्रष्टाचार इस साल भी नहीं दूर हुआ। यहां तक कि पल्लेदारी में भी धन उगाही की गई। समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल तो हुई पर कुछ घण्टों के लिए प्रभावित कार्यप्रणाली बाद में वही समस्या, वही भ्रष्टाचार।

किसानों की नजर में अनिवार्य प्रश्न यह है कि उनके लिए तयशुदा कीमत और खरीद मात्रा में आखिर चंदौली में चलने वाला यह भ्रष्टाचार आखिर कब समाप्त होगा। इन किसानों की समस्या आखिर कब खत्म होगी ? क्या यह सवाल अनिवार्य प्रश्न बनकर समाज के सामने व प्रशासन की व्यवस्था के सामने हमेशा खड़ा रहेगा?

हमारे अन्नदाता किसान उत्तर खोज रहे हैं आज ही नहीं दशकों से।

# चन्दौली के डी.एम. नहीं देखते व्हाट्सएप संदेश, तो फिर क्यों इंस्टाल है उनके नम्बर पर व्हाट्सएप

अनिवार्य प्रश्न, ब्यूरो संवाद। चंदौली। स्थानीय जिला अधिकारी का व्हाट्सएप नंबर चलता तो है पर उस पर कोई संदेश देखा नहीं जाता। केंद्र और राज्य सरकार जहां जनता से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया व डिजिटल माध्यम का सहारा ले रही है वहीं जनपद का सुन्न व बेहोश प्रशासन अभी तक सुस्त और सोया हुआ ही है। वैसे तो जनपद के जिला अधिकारी का नंबर 9454417576 व्हाट्सएप पर सक्रिय है, उसपर उनकी डी.पी. भी लगी है और डाटा सेवा ऑन होने से संदेश की डिलीवरी भी होती है लेकिन संदेश पढ़ा नहीं जाता है। हांलांकि किसको जनता के द्वारा भेजे गए संदेशों के फिक्र है, साहब तो डीएम हैं वह किसी का संदेश क्यों देखेंगे?

आम लोगों द्वारा भेजी गई सूचना पर जब अनिवार्य प्रश्न समाचार समूह ने भी संदेश भेजा तो संदेश डिलीवर तो हुआ मगर काफी दिनों तक पढ़ा नहीं गया। संभवतः उनके नंबर पर किसी का भी डिलीवर संदेश देखा नहीं जाता। हो सकता है किसी विभाग का या किसी अधिकारी का देखा भी जाता हो पर आम आदमी के नंबरों से भेजे गए संदेश को पढ़ा नहीं जाता।

उल्लेखनीय है कि चन्दौली के वर्तमान जिलाधिकारी आईएएस संजीव सिंह हैं। प्रशासनिक महकमें में उन्हें एक युवा, उर्जावान और सक्रिय अधिकारी के रुप में जाना जाता है।

यहां अनिवार्य प्रश्न है कि जब मीडिया समूहों द्वारा भेजा गया समाचार, विषय प्रकाशन व शिकायतें नहीं देखी जातीं तो आम आदमी की प्रार्थना कैसे देखी या पढ़ी जाती होगी। ऐसे में जिलाधिकारी के उस नंबर पर व्हाट्सएप बनाया ही क्यों गया है। क्या सिर्फ मुख्यालयों के दबाव और खानापूर्ति के लिए व्हाट्सएप इंस्टाल किया गया है। या उसका कोई और औचित्य है?

अनिवार्य प्रश्न यह भी है कि आखिर यह नंबर चलाता कौन है? अगर डीएम साहब का नियुक्त कोई पीआरओ चलाता है तो क्या उनके नंबर पर आए विभिन्न संदेशों को अवॉयड करता है या सिर्फ अपने चिर परिचितों का ही संदेश पढ़ता और उसका जवाब देता है? आम आदमी ऐसे अनेक सवालों को लेकर खड़ा है। अपनी हजारों पीड़ायें साहब डीएम से उक्त व्हाट्सएप नम्बर और इस सरल माध्यम से साझा करना चाहता है, लेकिन हाय, सरकार तो हमारी जरूर है पर आज भी चलती अंग्रेजी प्रणाली से ही है। जनता समाज के भरोसे जीती आई है और समाज के भरोसे जीती रहेगी। सरकारें जो करती आईं हैं सरकारें वही करती रहेंगी। ऐसे में एक बड़ा अनिवार्य प्रश्न यह है कि यह प्रशासन किसका है और किस लिए है? ये सरकारी लोग कौन हैं? क्या कर रहे हैं और किसके लिए हैं? आखिर आम आदमी अपनी बात इन तक कैसे पहुँचाए?

◆ ◆ ◆

वर्ष 4, अंक 02, फरवरी 2022
www.anivaryaprashna.in
अनिवार्य प्रश्न
हर कलम बिकती नहीं।

# राजनारायण पार्क का नाम बेनियाबाग प्रयोग करने पर सपाई नाराज

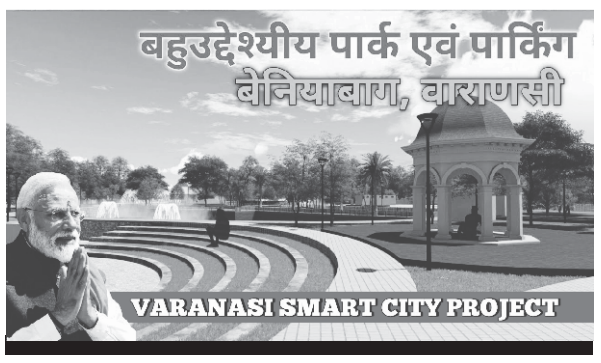


वाराणासी। लोकतंत्र सेनानी राजनारायण का नाम स्मार्ट सीटी प्रोजेक्ट के तहत संवारे गए बेनियाबाग पार्क से हटाए जाने का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। सपा का एक प्रतिनिधि मंडल वाराणसी के मण्डल कमिश्नर दीपक अग्रवाल से मुलाकात कर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौपा। सपा में पूर्व मंत्री मनोज राय ने बताया कि बेनियाबाग पार्क का नाम लोक बंधु राजनारायण के नाम से था जिसे भाजपा सरकार ने परिवर्तित कर बेनियाबाग कर दिया है, सपा इसके साथ नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं।

उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत ने यहां विक्टोरिया की प्रतिमा लगाई थी। उस प्रतिमा को गुलामी का प्रतीक मानते हुए लोकबंधु राजनारायण ने न सिर्फ आंदोलन किया बल्कि उसे तोड़ भी दिया था। प्रतिमा तोड़े जाने के बाद उन्हें तीन माह की जेल हुई थी। बाद में इस पार्क का नाम बेनियाबाग कर दिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर मुलायम सिंह यादव की सरकार में पार्क का नाम राज नारायण स्मारक पार्क कर दिया गया था। तब से पार्क उसी नाम से जाना जा रहा था। राज नारायण जी काशी के गौरव थे। विकास योजनाओं के दौरान इस पार्क को फिर से बेनियाबाग का नाम दिया जा रहा है जिसे लेकर लोगों में रोष है।

विगत दिनों मण्डलायुक्त ने पूर्व मंत्री व सपजनों को भरोसा दिलाया कि जैसे पूर्ववत नाम था उसी तरह कर दिया जाएगा। पत्रक सौपने वालों में प्रमुख रूप से मनोज राय, जिलाध्यक्ष सुजित यादव, सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव संदीप सिंह, विधानसभा अध्यक्ष अजय चौधरी , वरिष्ठ नेता हरीश सिंह, राजू यादव, पूजा यादव, विमलेश यादव, मनोज यादव गोलू, पुष्पा चौपाल, नीलू पाण्डेय, जयराम यादव, वरिस्ठ नेता मनीष सिंह, आदि लोग शामिल थे।

# विकसित भारत के नागालैण्ड में हुई गुलेल प्रतियोगिता

**गुलेल नगा जनजातियों का एक परंपरागत और पसंदीदा खेल है।**

अनिवार्य प्रश्न। संवाद। नई दिल्ली। 'जनजातीय गौरव दिवस' के सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत केंद्र और राज्य सरकारों, जनजातीय शोध संस्थानों और अन्य सहयोगी संगठनों द्वारा देशभर में कई कार्यक्रमों और समारोहों का आयोजन किया गया।

इन कार्यक्रमों और आयोजनों का उद्देश्य जनजातीय लोगों की उपलब्धियों और योगदानों के साथ उनकी संस्कृति और अनोखी परंपराओं को दुनिया के सामने लाना था। इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में राज्य स्तरीय एक अनोखी गुलेल प्रतियोगिता का आयोजन नगालैंड की राजधानी कोहिमा के हेरिटेज विलेज किसामा में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया।

नगालैंड के विभिन्न नगा जनजातियों के प्रतिस्पर्धियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गुलेल नगा जनजातियों का एक परंपरागत और पसंदीदा खेल है। इस कार्यक्रम में 25 नगा जनजातियों ने बेहद उत्साह और जोश के साथ हिस्सा लिया। खेल के हर एक शॉट के बाद लोगों ने तालियां बजाकर प्रतिस्पर्धियों का उत्साह बढ़ाया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रतिस्पर्धी परंपरागत जनजातीय वस्त्रों में थे।

इस प्रतिस्पर्धा के प्रथम तीन विजेताओं को नकद पुरस्कारों के साथ प्रशस्तिपत्र भी दिया गया। प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन नगालैंड सरकार के अतिरिक्त सचिव नचुंबेमो लोथा ने किया।

# ट्रांसपोर्टरों व व्यापारियों को दश गुना की जगह दो गुना जुर्माना

**टोलप्लाजा पर ओवरलोड वाहनों से दश गुने जुर्माने से आजादी**

अनिवार्य प्रश्न। संवाद। वाराणसी। पिछले दिनो ओवरलोडिंग से तेजी खराब हो रही सड़कों के लिए सरकार ने 10 गुना शुल्क वसूली का एक कठोर नियम लागू किया था। देशभर में इसको लेकर कई बार ट्रांसपोर्टर और व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया।

देशभर में व्यापार पर संकट और बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए केन्द्र सरकार ने व्यापारियों को खुश करने के लिए ओवरलोडिंग से 10 गुना वसूली हटाकर मात्र दोगुना जुर्माने को तत्काल लागू करने के आदेश दिए हैं। यह नया नियम लागू होने से देश भर में सामग्री के दामों में कमी हो सकती है। इस फैसले का लाभ सीधे जनता को मिलने वाला है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव को देखते हुए कमजोर आत्मबल की सरकार ने जनता को झांसे में लिया है। पहले 10 गुना वसूल लिए अब दोगुना से ही संतोष करेंगे।

सच्चाई यह है कि वर्ष 2017 में योगी सरकार ने ओवरलोडिंग रोकने के लिए कठोर कदम उठाते हुए अपने अधीनस्तों को इसके लिए विशेष रुप से निदेशित किया था। उसके बाद के वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के सभी टोलप्लाज़ा पर ओवरलोडिंग के अपराध के वाहनों के लिए 10 गुना तक जुर्माने का नियम लागू कर देने के साथ ही अधिक माल वहीं गिरा देने का कठोर नियम शुरू कर दिया। जिसके बाद काफी नियंत्रण भी हुआ। हांलाकि इसका विरोध भी खूब हुआ लेकिन सरकार तनिक नहीं झुकी। अब चुनाव के समय उसे जनता से डर लग रहा है।

# तनख्वाह मांगने पर मालिक ने जिंदा जलाया

अनिवार्य प्रश्न। संवाद। पटना। बिहार आज भी दबंगई की जद में ही है। यह तब साबित हो गया जब पटना में एक युवक को जिंदा जला देने का मामला सुर्खियों में आया।

विगत दिनों मोबाइल के एक दुकानदार पर एक युवक की हत्या का आरोप लगा। उक्त दुकानदार ने एक मोबाइल के एसेसिरीज की चोरी का आरोप लगाकर एक युवक पर पेट्रोल गिराकर ज़िंदा जला दिया। मृतक की पहचान विकास राम के रूप में हुई है।

वह सिपारा का रहने वाला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सूत्रों के अनुसार मृतक व्यक्ति मोबाइल रिपेयरिंग की उसी दुकान में नौकरी करता था। उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि वह दुकानदार कई महीने से मृतक युवक की पगार नहीं दे रहा था। युवक काफी समय से वेतन मांग रहा था पर नहीं मिल रहा था। मृतक के परिवारीजनों ने पुलिस से बताया की दुकान मालिक ने युवक से ही पेट्रोल मंगवाया और उसपर छिड़ककर फिर उसमें आग लगा दी।

वह युवक धू–धू कर चलने लगा तब उसको काफी गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया और फिर भर्ती कराया गया। जहां उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई।

युवक की मौत के बाद क्षुब्ध परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। बेउर थाना क्षेत्र समेत चार थानों की पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद बल पूर्व जाम हटवाया। परिजनों की मांग थी कि हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और मुआवजा दिया जाय।

# अब पौधा लगाने पर ही मिलेगी बिल्डिंग बनाने क इजाजत : शिव राज

अनिवार्य प्रश्न, संवाद। भोपाल। अब बिल्डिंग परमिशन इसी शर्त पर दी जाएगी कि मकान बनाने वाला व्यक्ति एक पेड़ अवश्य लगाएगा। नगर निगम हो, नगर पालिका या नगर पंचायत अर्थात जिस भी स्तर का नगरीय निकाय हो बिल्डिंग परमिशन के लिए पौधा लगाने की शर्त अनिवार्य होगी। घर पर जगह न होने की स्थिति में पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना और उसकी सुरक्षा करना आवश्यक होगा। उक्त बातें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशव्यापी अंकुर वृक्षारोपण अभियान को शुभारंभ करते समय प्रदेश को संबोधित करते हुए कहा था।

निवास से वर्चुअली आरंभ इस कार्यक्रम में किसान–कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल उपस्थित थे। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कार्यक्रम में वर्चुअली मंदसौर से सहभागिता की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 5 जिलों के अंकुर अभियान के जिला नोडल अधिकारियों से वी.सी. द्वारा संवाद किया। कार्यक्रम में हरदा में वृक्षारोपण गतिविधियों का फिल्म द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने अंकुर कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गाँवों में भी ग्राम पंचायतों की यह जिम्मेदारी होगी कि जो भी मकान बने, उसमें एक पेड़ अवश्य लगे। यह शर्त प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले आवासों पर भी लागू रहेगी। घरों के अलावा स्कूल, पंचायत भवन, खेत आदि में पेड़ लगाए जाएंगे। सरकारी भवनों और कार्यालयों के लिए भी यह शर्त रहेगी। मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में जितने फ्लैट बनेंगे, उतने पेड़ बिल्डर को लगाने होंगे। सभी शासकीय, गैर–शासकीय भवनों के निर्माण में पेड़ लगाने की शर्त जोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि व्यक्ति स्व–प्रेरणा से भी पेड़ लगाएंगे, क्योंकि पर्यावरण सुधार हमारे लिए नारा नहीं मंत्र है।

# महिलाएं एकजुट हों, बदलें यूपी : प्रियंका गांधी

अनिवार्य प्रश्न। संवाद। लखनऊ।उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कांग्रेस द्वारा 'लड़की हूं लड़ सकती हूं', शक्ति संवाद, कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गाँधी वाड्रा ने महिलाओं, लड़कियों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में प्रदेश की नारी शक्ति ने अपनी बात रखी और प्रियंका गाँधी वाड्रा ने उनके सवालों का जवाब दिया और सरकार में आने पर समाधान का वादा किया।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राज्य की सारी महिलाएं एकजुट होकर राजनीति को बदलने की कोशिश करें। आजकल की जो राजनीति चल रही है कि वचन दिया और रखा नहीं, धर्म के आधार पर राजनीति कर ली, जाति के आधार पर वोट मांग लिया उसके बाद आपके लिए कोई काम नहीं किया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाएं समझें कि किस तरह की राजनीति हो रही है। और उसे बदलने के लिए शक्ति आप सब में है, इसीलिए हमने जो घोषणा पत्र बनाया है, उसमें मोबाइल और स्कूटी सिर्फ माध्यम हैं, महिलाओं को सुरक्षित रखने और सशक्त बनाने के लिए। हमने बहुत सी घोषणाएं की हैं, जिनको पूरा करने का हम वचन दे रहे हैं। हमारा एक गारंटी कार्ड भी है, जो घर–घर तक पहुँचाया जाएगा।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, कि महिलाओं को हम पर भरोसा करना पड़ेगा। यह महिलाओं का हक़ है कि सरकार उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए काम करे। खेलों में महिलाओं में बहुत क्षमता है, उन्हें सारी सुविधाएं मिलें तो वह बहुत अच्छा कर सकती हैं। हम एक पूरा विधान निकालने वाले हैं, जिसमें भर्तियां निकालने, रोजगार देने का अपना रोडमैप बताएँगे। उत्तर प्रदेश में काफी वेकेंसियां हैं, जो भरी नहीं गई हैं। विधानसभा चुनाव में चालीस फीसद महिलाओं को टिकट देना हमारी बड़ी पहल है। जबसे हमने लड़कियों का मुद्दा उठाया तब से दूसरी पार्टियां भी जाग गई हैं कि आधी आबादी महिलाएं हैं। अचानक अब मोदी जी ने पहली बार सिर्फ महिलाओं की रैली की, अखिलेश जी ने महिलाओं के लिए घोषणाएं की। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग समझने लगे हैं कि महिलाओं की एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। अगर हम उत्तर प्रदेश में क्रांति लाएंगे, तो मैं दावा कर सकती हूँ कि संसद भवन में भी लोग इसे नकार नहीं पाएंगे। हमारी पार्टी ने घोषणा की है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को दस हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा, साथ ही प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

कहा कि मैंने सभी बहनों की समस्याओं को सुना, महिलाओं को उनका हक़ नहीं दिया जा रहा है। सरकार की विचारधारा और मानसिकता यही है कि एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया और जिम्मेदारी ख़त्म। आप सशक्त कैसे होंगी, आपकी शिक्षा कैसे होगी, आप के लिए रोजगार कैसे मिलेगा, यह सब नहीं पूछा। वो सोचते हैं कि सिर्फ एक गैस सिलेंडर देने से आप उन्हें वोट दे देंगी। इसी तरह से जब भी चुनाव में आपके सामने आते हैं महिलाओं की भलाई और उनके सशक्तिकरण की बातचीत नहीं करते हैं। इन सबकी मानसिकता महिलाओं को नकार देना है। मैं कहती हूँ कि आप इस देश की आधी आबादी हैं, महिलाओं को अब कोई नकार नहीं सकता है। अनेक बेटियां, महिलाएं संघर्ष कर रही हैं पर उन्हें पहचानने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ, कि आप में शक्ति है, उसे पहचानिए, आपके लिए लड़ने कोई नहीं आ रहा है, आप खुद लड़ेंगी।

# राजस्थान में गधों की हुई चोरी

**गधे स्वामियों का थाने पर धरना, पुलिस हलकान**

अनिवार्य प्रश्न। संवाद। जयपुर। गत महीने हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में गधों की चोरी का अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। जिसके बाद सुनने वाला हर शख्स हैरान है। बताया जा रहा है कि हनुमानगढ़ के खुईयां थाना इलाके से चोरों ने गत माह में कुल 70 गधों की चोरी की लिए।

गधों के स्वामियों के थाने पर धरना देने के बाद पुलिस परेशान हो गई। गधा मालिकों के थाने पर धरना देने के बाद पुलिस एक्सन में आई। गहन तलाशी अभियान चलाने के बाद पुलिस ने 15 गधों को ढूंढ़ लिया। लेकिन धरना दे रहे मालिकों ने उनके सारे गधे नहीं होने से उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वह अपने गधे लेकर ही यहाँ से जाएंगे।

# हो गया, दुनिया का सबसे महंगा तलाक

**दुबई के अरबपति शासक शेख मोहम्मद बिन राशीद अल मकतूम पर इस मुकदमे के सेटेलमेंट के लिए 55 करोड़ पाउण्ड की देनदारी आई है।**

फीचर डेस्क। जॉर्डन के पूर्व राजा हुसैन की बेटी राजकुमारी हया बिंत अल हुसैन का तलाक जो दुनिया का लगभग सबसे महंगा तलाक कहा जा रहा है अब हो गया है। ब्रिटेन के अब तक के परिवार से जुड़े विवादों में यह सबसे महंगा तलाक कहा जा रहा है। राजकुमारी हया बिंत अल हुसैन को ब्रिटेन के हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 5500 करोड़ रुपए की अधिकार राशि मिलेगी। शेख मोहम्मद बिन राशीद अल मकतूम की पत्नी हया अब उनके रिश्ते से मुक्त हो गई हैं।

ब्रिटेन के हाई कोर्ट में चल रहे परिवार के वादों में यह मुकदमा अब परिवार के विच्छेदन के बाद समाप्त हो गया है। शेख मोहम्मद बिन राशीद अल मकतूम यूएई के प्रधानमंत्री हैं। राजकुमारी हया उनकी छठवीं पत्नी थीं। बताया जा रहा है कि दोनों में विवाद के लिए शेख मोहम्मद बिन राशीद अल मकतूम की एक दूसरी पत्नी की बेटी जिम्मेदार है। हालांकि यह मामला इतना आगे बढ़ा कि सुलझाया नहीं जा सका और अंततः इसे ब्रिटेन के हाई कोर्ट में तलाक तक जाना पड़ा।

उल्लेखनीय है कि राजकुमारी हया लगभग 47 साल की हैं और शेख मखदूम को बच्चों के लिए भी बड़ी राशि देनी पड़ी है। दुबई के अरबपति शासक शेख मोहम्मद बिन राशीद अल मकतूम पर इस मुकदमे के सेटेलमेंट के लिए 55 करोड़ पाउंड की देनदारी आई है। यह भारतीय रुपए में लगभग 5500 करोड़ या 55 अरब रुपए बैठती है। गत वर्ष के आखिरी में सेटलमेंट हुए इस केस में 25 करोड़ पाउण्ड की राशि तय की गई थी।

# मलिन बस्ती के कुल 3.61 लाख घर निर्माण को मंजूरी

फाईल फोटो

**प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 1.14 करोड़ हो गई है, जिनमें से 89 लाख से अधिक का निर्माण जारी है और 52.5 घरों के निर्माण कार्य को पूरा कर लाभार्थियों को वितरित किया गया है। मिशन के तहत कुल निवेश 7.52 लाख करोड़ है।**

अनिवार्य प्रश्न। संवाद। नई दिल्ली। प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) की केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 56 वीं बैठक कल गत वर्ष नई दिल्ली में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के सचिव, दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। पीएमएवाई –यू के सहभागिता में किफायती आवास, लाभार्थी उन्मुख निर्माण, साथ ही लम्बवत मलिन बस्ती पुनर्विकास के तहत कुल 3.61 लाख घरों को निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए, आवास एवं शहरी कार्य सचिव ने मिशन के तहत घरों के निर्माण के संबंध में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मुद्दों को उठाया। उन्होंने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से बिना देरी किए ऐसे मुद्दों का समाधान करने को कहा ताकि घरों के निर्माण में तेजी लाई जा सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के अंतर्गत घरों का निर्माण विभिन्न चरणों में चल रहा है। इसके साथ ही मिशन के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 1.14 करोड़ हो गई है, जिनमें से 89 लाख से अधिक का निर्माण लिए जारी है और 52.5 लाख घरों के निर्माण कार्य को पूरा कर के लाभार्थियों को वितरित किया गया है।

मिशन के तहत कुल निवेश 7.52 लाख करोड़ है और जिसमें 1.85 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता के रूप में हैं। अब तक, 1.13 लाख करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति ने 14 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से 3.74 लाख घरों के निर्माण में अंतरित होने वाली परियोजनाओं के संशोधन के लिए भी मंजूरी दी है।

इसके अलावा सचिव, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएमएवाईयू के तहत देश भर में आवास निर्माण में तेजी लाने और निर्धारित समय के भीतर पूरा करने पर जोर दिया ताकि 2022 तक 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

खबरों के लिए लाग इन करें :
www.anivaryaprashna.in

# बार बार स्वेच्छाचारिता करता पाया जा रहा है आजमगढ़ के महाराजगंज का थानेदार

योगी राज में पुलिस की गुंडई

अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद। आजमगढ़। जिले के महाराजगंज थाने का थानेदार लगातार स्वेच्छाचारिता करते सुर्खियों में आ रहा है। यहां तक कि अब उसकी शिकायत जिलाधिकारी कार्यालय व पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक भी नगरवासी करने लगे हैं। प्रकाश में आए नए मामले में एक संविदा कर्मी पर उक्त थाना अंतर्गत गोरखपुर गांव के ग्राम प्रधान के द्वारा धमकाये जाने की शिकायत पर सनकी थानेदार ने उल्टे संविदा कर्मी पर ही दबाव बनाकर मामले को रफा–दफा करने के लिए कोशिश करने लगा।

इससे पूर्व एक मामले में महाराजगंज थाने का थानाध्यक्ष पत्रकारों के साथ अभद्र आचरण करते पाया गया था।

संविदा कर्मी के पक्ष के अनुसार गांव में विद्युत कार्य हुआ था, जिसके लिए बिजली के खंभे को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर लगाया जाना था। संविदा विद्युत कर्मी पंकज गौड़ के द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार ग्राम प्रधान ने बिजली कटौती के संबंध में तत्काल मरम्मत के लिए दबाव डाला एवं तुरंत ठीक करने के लिए अपशब्द कहते हुए गंदी–गंदी गालियों की बौछार की। साथ ही मारने की धमकी तक दिया। ऐसे में लाइनमैन ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की लेकिन प्रधान आगबबूला होकर भड़कता रहा। जब इसकी शिकायत संविदा कर्मी व संबंधित संगठन के लोग महाराजगंज थाने पर लेकर गए तो थानाप्रभारी ने दबंग प्रधान पर विधिक कार्यवाही करने की जगह शिकायतकर्ताओं को ही डांट कर भगा दिया। योगी राज में भी आजमगढ़ में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों का रवैया नहीं बदल रहा है। ऐसा लगता है आजमगढ़ के पुलिस विभाग के अधिकारियों की मानसिकता अभी भी नहीं बदली है।

उक्त घटना व सनकी थानेदार के रवैए को लेकर जब संविदा कर्मियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया तो जिला अधिकारी से निर्देश हुआ कि पुलिस अधीक्षक के यहां शिकायत करें। उनके पास जाने पर पुलिस अधीक्षक अनुपस्थित मिले।

आजमगढ़ की प्रशासनिक कहानी तो अब राम ही जाने लेकिन संविदा कर्मियों की परेशानी का अभी जल्दी हल मिलते नहीं दिख रहा है।

ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां की स्थानीय प्रशासनिक विकृति को ध्यान में रखते हुए यहां के प्रशासनिक बागडोर को थोड़ा कड़ा करने की जरूरत थी और यहां से निकम्मे कर्मचारियों को तत्काल दरबदर करने की जरूरत थी। नागरिकों व संविदा कर्मियों ने बताया है कि आजमगढ़ में आम आदमी के शिकायतों की सुनवाई बड़ी शिथिल हो गई है। अधिकारी जगह–जगह मनमाना कर रहे हैं।

किसी थाना विशेष से बार–बार इस तरह की शिकायत आनी वहां के थाने पर लगातार हो रही घटनाओं के बारे में व भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। ऐसे थानेदार एक जगह कम ही दिन रह पाते हैं और जनता का विरोध प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में थानेदार पर कार्यवाहिओं की गाज गिर सकती है। आने वाली सरकार में अनिवार्य प्रश्न यह है कि ऐसे अधिकारी कब तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं और कब नपते हैं देखना बड़ा दिलचस्प होगा।

◆◆◆

# लगातार पांचवीं बार स्वच्छता का खिताब

अनिवार्य प्रश्न। संवाद। नई दिल्ली। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने विगत दिनो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन–शहरी 2.0 के भाग के रूप में आयोजित किए गए स्वच्छ अमृत महोत्सव में भारत के सबसे स्वच्छ शहरों के विजेताओं को सम्मानित किया। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) के विभिन्न पहलों के अंतर्गत कस्बों व शहरों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वच्छता के लिए अपनाए गए अच्छे कार्यों की पहचान करने के लिए किया गया, इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, सफाई मित्र सुरक्षा चौलेंज और शहरों के लिए कचरा मुक्त स्टार रेटिंग के प्रमाणपत्र जैसे विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 300 से ज्यादा पुरस्कारों का वितरण किया गया।

लगातार पांचवें वर्ष, इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने के खिताब से सम्मानित किया गया, जबकि सूरत और विजयवाड़ा ने '1 लाख से ज्यादा आबादी' की श्रेणी में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर सफलता प्राप्त की।

'1 लाख से कम' जनसंख्या वाली श्रेणी में, वीटा, लोनावाला और सासवड क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे और सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं। वाराणसी 'सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर' के रूप में उभरकर सामने आया, जबकि अहमदाबाद छावनी ने 'भारत की सबसे स्वच्छ छावनी' का खिताब जीता, इसके बाद मेरठ छावनी और दिल्ली छावनी को यह स्थान प्राप्त हुआ।

होशंगाबाद (मध्य प्रदेश),'फास्टेस्ट मूवर' की श्रेणी में'फास्टेस्ट मूवर सिटी' ('1 लाख से ज्यादा आबादी' श्रेणी में) के रूप में उभरा, जो 2020 की रैंकिंग में 361 वें स्थान से 274वें स्थान की छलांग के साथ इस वर्ष 87वें स्थान पर अवस्थित है, इस प्रकार से उसने शीर्ष 100 शहरों में अपना स्थान प्राप्त कर लिया है।

राज्य पुरस्कारों में, छत्तीसगढ़ लगातार तीसरे वर्ष '100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों" की श्रेणी में 'सबसे स्वच्छ राज्य' के रूप में उभरा, जबकि झारखंड ने दूसरी बार "100 से कम यूएलबी श्रेणी" में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता।

कर्नाटक और मिजोरम क्रमशः बड़े (100 से अधिक यूएलबी) और छोटे (100 से कम यूएलबी) राज्य की श्रेणी में "फास्टेस्टमूवर स्टेट्स' बन कर उभरे।

पुस्तकों के इतिहास में बड़े स्वरुप के लोकार्पण के लिए विश्व की पहली किताब बनी

# 'तस्वीर-ए-हर्फ'

अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद।

वाराणसी। नगर के जेल गूलर स्थित मदर हलीमा सेंट्रल स्कूल में स्याही प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उर्दू काव्य संग्रह तस्वीर–ए–हर्फ का लोकार्पण किया गया। यह किताब बनारस के ख्याति लब्ध शायर मिर्जा अतहर हुसैन 'अतहर' बनारसी ने लिखी है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित सज्जनों में वतौर अध्यक्ष उर्दू विभाग बीएचयू के पूर्व अध्यक्ष डा. याकूब यावर मुख्य अतिथि डॉ. अफजाल मिस्बाही असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू विभाग बीएचयू, विशिष्ट अतिथि मौलाना नसीर सिराजी, मौलाना जहीन हैदर साहब 'दिलकश' गाजीपुरी एवं 'स्याही प्रकाशन' के निदेशक व साहित्यकार छतिश द्विवेदी 'कुंठित' मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन जामिया अस्पताल बनारस के सीएमओ डॉ सफीक हैदर ने किया। लोकार्पण कार्यक्रम में अनेक जनपदों के साहित्यकार शामिल हुए।

यह किताब उर्दू लिपि में लिखी गई एक मुकम्मल काव्य संग्रह है। सभा के अध्यक्ष व उर्दू विभाग बीएचयू से सेवानिवृत डॉक्टर याकूब यावर ने कहा कि उर्दू लिपि में प्रकाशित यह किताब उर्दू भाषा को और मजबूत बनाने में असरदार काम करेगी। साथ ही यह किताब उन लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए जो उर्दू के विद्यार्थी हैं और साहित्य के प्रेमी हैं। क्योंकि यह किताब एक दीवान है और दीवान में सभी तरह की ग़ज़लों व नज्मों का समावेश होता है। हर अदीब के लिए यह किताब उपयोगी साबित होगी। कार्यक्रम में अपने किताब पर बोलते हुए अतहर बनारसी ने कहा कि यह किताब मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

मैंने अपने जीवन की समाप्ति के लिए एक बार प्रयास किया था। लेकिन बच जाने के बाद यह किताब लिखी है। मैंने पूरी कोशिश की है कि तस्वीर–ए–हर्फ उर्दू जबान में लिखी गई एक अच्छी और मुकम्मल किताब बन सके। मैंने अपने जीवन में अर्जित अनुभवों व तालीम को इस किताब में उतारने की पूरी कोशिश की है। अब लोग यह तय करेंगे कि यह किताब कितनी उपयोगी व सफल बन पायी है। वैसे मैंने अपनी सभी पीड़ा व संवेदनाओं को इसमें सजो दिया है।

आखिरी में धन्यवाद ज्ञापन व प्रकाशकीय संबोधन में प्रकाशन के अधिष्ठाता व साहित्यकार छतिश द्विवेदी 'कुंठित' ने अपने दो शब्द में कहा कि एक जीवन समाप्त करने की विफल कोशिश करने के बाद दूसरे जीवन में लिखी गई यह किताब लेखक को तीसरी जिंदगी दे देती है।

अब लेखक अपने पुस्तक के रूप में शुरू हो रही इस तीसरी जिंदगी को किसी नींद की गोली से मार नहीं सकता। अब यह किताब लेखक को अमर कर देगी। उर्दू लिपि में लिखी गई यह किताब समाज के लिए आगामी पुस्तकों के प्रकाशन में मील का पत्थर साबित होगी। उर्दू भाषा के जानकार लोगों के लिए यह किताब एक अध्ययन सामग्री है। यह पुस्तक उर्दू के अनेक काव्य विधाओं से परिचित कराएगी।

साहित्यकार, शायर व एक शिक्षक के द्वारा लिखी गई यह किताब आगामी कई पीढ़ियों को उर्दू भाषा एवं लिपि के साथ ही उर्दू साहित्य की विधा तथा अच्छी शायरी से परिचय कराती रहेगी। श्री 'कुंठित' ने अपने जीवन में उर्दू प्रेम को लेकर भी काफी भावनाएं साझा किया।

सभा में साहित्यकारों में सुनिल सेठ, आशिक बनारसी, खलील अहमद राही, डा. लियाकत अली, शिवकान्त गोस्वामी, विवेक गोस्वामी के साथ सेन्ट्रल स्कूल के निदेशक मण्डल के लोग मौजूद रहे।

# उर्दू की पुस्तक लोकार्पित

**साहित्यकार, शायर व एक शिक्षक के द्वारा लिखी गई यह किताब आगामी कई पीढ़ियों को उर्दू भाषा एवं लिपि के साथ ही उर्दू साहित्य की विधा तथा अच्छी शायरी से परिचय कराती रहेगी**

# हनुमत सतक पुस्तक का हुआ लोकार्पण

काशी के तीन मुर्धन्य कवियों व साहित्यकारों का सम्मान

अवधी काव्य संग्रह लोकार्पित करते साहित्यकार

अनिवार्य प्रश्न। ब्यूरो संवाद। वाराणसी। स्याही प्रकाशन परिसर भोजूबीर–सिंधोरा रोड वाराणसी में 'उद्गार' साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित की गई कवि गोष्ठी में वाराणसी के जिला प्रशिक्षण अधिकारी दीनानाथ द्विवेदी रंग द्वारा लिखित अवधी की काव्य पुस्तक 'हनुमत सतक' का लोकार्पण किया गया। यह किताब वाराणसी के स्याही प्रकाशन से प्रकाशित की गई है। पुस्तक में भगवान श्री हनुमान पर 100 घनाक्षरियां संयोजित की गई है। कवि अपने जीवन के अथाह पीड़ा के काल में प्रभु को याद करते हुए इन्हें रचा था। पुस्तक को पढ़ते हुए कवि का अवधी भाषा के ऊपर अधिकार साफ–साफ जाहिर होता है। संस्कृत व हिन्दी में अनेक शतक लिखे गए हैं किन्तु अवधी में सतक का बड़ा अकाल है। कवि के इस प्रयास व स्याही प्रकाशन के प्रकाशकीय योगदान को अवधी भाषा की भक्ति गीत व घनाक्षरी परम्पारा में एक मील के पत्थर के रुप में देखा जा रहा है। अवधी भाषा के घटते चलन के दौर में इस भाषा व घनाक्षरी विधा में सतक का लेखन लेखक को संकलनीय बना देता है। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश चंद्रभाल सुकुमार, जिला पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष कंचन सिंह परिहार रहे और अध्यक्ष साहित्यकार मधुकर मिश्र रहे। कार्यक्रम का संचालन बुजुर्ग कवि योगेन्द्र नारायण चतुर्वेदी 'वियोगी' ने किया। इस लोकार्पण व कवि गोष्ठी के लिए स्वागत् व आभार ज्ञापन उद्गार के संस्थापक व प्रबंधक छतिश द्विवेदी कुंठित ने किया। लोकार्पण कार्यक्रम में अयोध्या के दिव्य प्रकाशन ने काशी के तीन मुर्धन्य कवियों का सम्मान भी किया। सम्मानित किये जाने वाले कवियों में क्रमशः कवि योगेन्द्र नारायण चतुर्वेदी 'वियोगी' को 'सरस्वती वरद पुत्र' सम्मान, साहित्यकार छतिश द्विवेदी 'कुंठित' को 'काव्य रत्न' एवं डा. लियाकत अली 'विरही' को 'काशी के रसखान' सम्मान से सम्मानित किया।

सभा के अन्तिम में प्रकाशकीय संवाद व्यक्त करते हुए छतिश द्विवेदी 'कुंठित' ने कहा कि अवधी का यह हनुमत सतक आचार्य तुलसीदास जी के ही तरह पूजाघर में सहेजने व आराधना के समय पाठ करने योग्य है।

आगे कहा कि आने वाले समय में विश्व का अवधी व हिन्दी भाषी समाज इसे अपने आध्यात्मिक जीवन में स्थान देगा। यह संरक्षणीय धर्म ग्रन्थ है। इसके बाद वे अपनी रचना पढ़कर सभी को आभार व धन्यवाद दिये।

# ठंड से चौकीदार और किसान की मौत

**थाने पर तैनात था चौकीदार और गेहूं सिंच रहा था किसान मध्यरात में हुई घटना**

अनिवार्य प्रश्न।संवाद। बलिया। जनपद के दो अलग–अलग स्थानों पर कड़ाके की ठंड से एक किसान और एक चौकीदार की मौत हो गयी। थाने में ड्यूटी के दौरान चौकीदार गिरकर बेहोश हो गया और किसान खेत मे सिचाई के दौरान अपना जीवन खो दिया।

सूत्रों के अनुसार दोनों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल ले जाने तक उन दोनों की मौत हो चुकी थी।

घटना चितबड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पलिगरा कला में देर रात कड़ाके की ठंड में नंद यादव उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र रूपनारायण यादव अपने खेत में गेहूं की जल सिंचाई कर रहे थे कि अचानक ही बेहोश हो कर गिर पड़े। वहीं पास बैठे उनके भतीजे ने देखा तो तत्काल मौके पर जाकर उठाने का प्रयास किया। सूत्रों के अनुसार पलिगरा कला निवासी नंद यादव को जब–तक घर ले आकर प्राथमिक उपचार होता तब–तक उनकी मौत हो चुकी थी।

दूसरी घटना सरियांव गॉव की है जो नगरा थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ के चौकीदार रामनाथ चौहान 58 थाने पर ड्यूटी पर थे। रात में तेज सर्दी के कारण अचानक गिर पड़े। वहां के थानाध्यक्ष नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गये, जहां चिकित्सकों ने चौकीदार को मृत घोषित कर दिया।

क्या आपके अन्दर भी धधक रही है?
सच्चाई को
अच्छाई को
भ्रष्टाचार को
शोषण को
अपराध को
सबके सामने लाने की आग?
तो निश्चिन्त होकर हमसे जुड़ें।
anivaryaprashna.in
अनिवार्य प्रश्न
अख़बार व वेब नेटवर्क
हर जिला व थाना में वैतनिक / अवैतनिक संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि की आवश्यकता है।
इच्छुक उम्मीदवार संपर्क करें।
9161099088
anivaryaprashna@gmail.com
हर कलम बिकती नहीं!

# क्या दुष्कर्म होते ही रहेंगे?

छतिश द्विवेदी कुंठित'
प्रधान संपादक व प्रकाशक

> जब तक प्रजातंत्र की अभिव्यक्तिओं को प्रसारित एवं संचारित करने से पहले उनका शुद्धीकरण नहीं किया जाएगा, शैक्षिक एकीकरण नहीं किया जाएगा, समान मानवीय विचारधारा के लोगों के निर्माण की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, अपने सांस्कृतिक धरोहर एवं विचार प्रेरकों को सजाया एवं उनका महिमा मण्डन कर प्रसारण नहीं किया जाएगा, जब-तक हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को समझने के लिए अलग से गुरुकुल नहीं बनायेंगे तब-तक सिर्फ द्वेष नहीं वाह्य प्रेरणाओं से भी दुष्कर्म होते ही रहेंगे।

काफी समय पहले की बात है, जब हम लोगों के संयुक्त परिवार में बूढ़े लोग हुआ करते थे। एक दिन एक नव बधू आई। उसका जोरों से स्वागत हुआ। जब उसका रसोई में प्रवेश हुआ तो पहले दिन की सुबह आज की चाय की जगह बनने वाला औषधीय गुणों वाला काढ़ा बनाकर उसने सबके सामने पेश किया। फिर क्या था जैसे पारिवारिक शोर का माहौल हो गया सभी एक सुर से नवबधू में खाना बनाने के गुण न होने की चर्चा करने लगे। सभी को यह लगने लगा कि वह महिला स्वादिष्ट भोजन बना नहीं पाएगी। जबकि सच्चाई कुछ और थी। पहले की महिलाएं काढ़ा बनाने के बाद चाय छानने वाली छननी के साथ में कपड़े का इस्तेमाल करके काढे को छानती थीं। लेकिन वह आधुनिकता का अनुभव करने वाली नववधू ने पद्धतियों को आते ही बदल दिया। उसने स्वच्छता का हवाला देते हुए पुराने कपड़े को हटवा दिया और केवल चाय जैसी वस्तु को छानने वाली छननी का प्रयोग किया। जिससे बहुत मोटे पदार्थों के अतिरिक्त छोटे कण भी तरल के साथ आ गए। परिवार के एक भी सदस्य ने इस बात को समझने पर ध्यान नहीं दिया। सब उस नवबधू के बिहार से आने, उत्तर प्रदेश के पाककला को ना जानने एवं पिछड़ा होने का हवाला देते हुए सिर धुनते रहे। यह घटना आज के हमारे सामाजिक संदर्भ का वह चित्रण है। जैसे चेहरे को दिखाने वाला आईना। हम अपने उस समय के हालात को देखते हुए उसको आज के सामाजिक संदर्भ से जोड़ना चाह रहे हैं। समाज, उसकी सोच, उसकी राय, उसका दृष्टिकोण एवं कहें तो उसका संपूर्ण वैचारिक एवं कायिक स्वरूप सबकुछ उस समाज में संचारित साहित्य के ऊपर निर्भर करता है। आज बहुत सारे अमानवीय विषयों पर हंगामा खड़ा हो जाता है, पर यह अमानवीय विषय घटित क्यों हुए हैं? इस पर कभी उतनी गहनता से विमर्श भी नहीं होते।

दिल्ली व मिर्जापुर में घटित या पिछले बरस बनारस, गाजीपुर, अलीगढ़, प्रतापगढ़, मुगलसराय, मुजफ्फरनगर, पश्चिम बंगाल का वह जनपद जहां नैतिकता का स्वांग है या कश्मीर का वह मामला जिस में कभी फैसला आया था। जगह कोई भी हो दुष्कर्म होते रहे हैं। यह दुष्कर्म सिर्फ हमारी बेटियों, बहनों एवं माताओं के साथ ही नहीं हुए, यह दुष्कर्म हमारे समाज के अन्य पहलुओं पर भी इसी प्रकार निंदनीय भावनाओं के साथ किए जाते रहे हैं। चिंता इस बात की भी ज्यादा की जानी चाहिए। इस प्रकार के दुष्कर्म कब रुकेंगे इसका दृढ़ जवाब किसी के पास नहीं है। हांलाकि हमारा इतिहास वासनात्मक प्रतिबंधों एवं उनको तोड़ने के अनेक उदाहरणों का इतिहास रहा है। हमारे कौरव पाण्डव के समय में भी द्रोपदी का चीरहरण प्रकारान्तर से दुष्कर्म ही था। तब उसके लिए हमारा समाज कितना बड़ा युद्ध करने पर प्रस्तुत हो गया। हम दुष्कर्म को कितना निंदनीय मानते हैं महाभारत इसका बहुत बढ़िया प्रमाण है। फिर भी आज–तक हम उस दुष्कर्म का उचित समाधान ढूंढ नहीं पाए, चाहे हम महाभारत कर लिए हों या हम किसी भी न्यायालय से बहुत बड़े दण्ड का प्राविधान कर छः लोगों को सजा ही करवा दिए या धनंजय चटर्जी जैसे अपराधियों को फांसी पर लटका दिए।

अतिराग, अतिद्वेष व नशे की बेहोशी दुष्कर्म के प्रमुख कारण रहे हैं। राजनीतिक गिरावट की वजह से समाधान नहीं निकाला जा सका। अगर शासक चाहते तो द्वेषपूर्वक किए जाने वाले दुष्कर्म के अलावा दूसरे कारण समाप्त किए जा सकते थे।

गड़बड़ियां तो और भी हैं। सही मायने में अगर समझा जाये तो हमारा साहित्य ही विकृत हो चुका है। हर साहित्य के प्रसारण और प्रकाशन से पहले छनन करने की जरूरत होती है। आज हमारे समाज में साहित्य को शुद्ध करने के लिए बहुत सारे कानून एवं विधान तय कर दिए गए हैं। इसके बाद भी इस तरह के साहित्य एवं उनका प्रसार हमारे समाज में है जो घिनौना है। एक दिन मैं लखनऊ के एक बुक स्टॉल पर गया। जो चारबाग में कुछ चुनिंदा बड़े पुस्तक भंडारों में गिना जाता है। वहाँ से कुछ किताबें एवं अख़बारों का संस्करण खरीदने का मेरा लक्ष्य था। मैं वहाँ जिस तरह के अश्लील साहित्य एवं उससे जुड़ी पत्र–पत्रिकाओं का खुला प्रदर्शन एवं बिक्री देखा, उसकी आवश्यकता उस प्रकार के प्रदर्शन व विक्री की कतई नहीं थी। हम सेक्स एजुकेशन के नाम पर सेक्स उत्प्रेरक तस्वीरें व साहित्य नहीं दे सकते। मगर इस समय अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में यही हो रहा है, चाहे कोई भी अख़बार, पत्र–पत्रिका व साहित्य हो। हांलाकि इनके ऊपर पंजीकरण एवं निगरानी के लिए बढ़ा तंत्र गठित है। इसके बाद भी कोई नहीं है जो वासनात्मक प्रेरकों को छापता और संचारित ना करता हो। जबकि सबका पक्ष यही है कि वह सेक्स एजुकेशन एवं रचनात्मक जागरूकता का अभियान चला रहे हैं।

वर्तमान समय में किताबों से भी अधिक अगर कोई चीज चलन में है तो वह है फिल्म। हमारी भारतीय फिल्में कई प्रकार के साहित्य का मिश्रण हैं। उनको चलचित्रों में डालकर सुबोधता के साथ नागरिकों को जीवन शैली सिखाया जाता है। सही अर्थों में अगर देखा जाए तो इस समय जितनी फिल्में बन रही हैं सभी में वासनात्मकता के अनेक विषय भरे रहते हैं। अश्लील संवाद और अश्लील क्लोजअप तस्वीरों के साथ उन्मुक्त और आजाद जीवन शैली का हवाला देते हुए जीवन के भिभिन्न विसंगतियों का फिल्मांकन कर दिया जाता है। जिन्हें हर हाल में समाज से दूर रखना चाहिए। इसके लिए सेंसर बोर्ड गठित है और उसके नाम पर भारी सरकारी धन का आवंटन है। लेकिन हमने आज तक एक भी फिल्म नहीं देखी जिस को सेंसर बोर्ड ने देखा व समाज की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए जिस को सुधारा हो। हर युवा जो अपना इतिहास और भविष्य नहीं जानता और वर्तमान को भी ठीक से समझ नहीं पा रहा उसके सामने आने वाली इस तरह की फिल्में उसमें किस तरह की मानसिकता को गढ़ेंगी। समाज एक शरीर की तरह है, उसमें विष डालने पर वह मर जाएगा। उसमें मद्धिम विष डालने पर वह धीरे–धीरे विकृत होने लगेगा और उसमें अमृत डालने पर उसकी आभा बढ़ जाएगी। हुआ यही है, समाज में विष भरा जा रहा है, मद्धिम विष। धीरे धीरे यह समाज को और हमारी न्याय पूर्ण मानवीय सांस्कृतिक संरचना को मार देगा।

कितनी पीड़ा की बात है कि आज आजादी के लगभग आठ दशकों बाद भी एक समुचित शिक्षा व न्याय प्रणाली गठित नहीं की जा सकी है। आज भी अनेक राज्यों में अलग–अलग शिक्षा व उसमें ली जाने वाली परीक्षा की मूल्यांकन प्रणाली भिन्न है। जब हमारे समाज में शैक्षिक एकीकरण नहीं है तो वैचारिक तथा मानसिक एकता कैसे संभव है। विकृत व कमजोर राजनीतिक व प्रशासनिक इच्छाशक्ति के कारण यह दुर्दशा हो रही है। यहाँ कहने में गुरेज नहीं करना चाहिए कि इससे बेहतर था हमारे राजाओं का शासन। कम से कम उनके राज्य में त्वरित न्याय था, शीघ्र सुनवाई थी, अगर वह सही को सही और गलत को गलत समझ लेते थे तो कम से कम आम आदमी को जल्दी अधिकार तो मिल जाता था, पर, आज सही को झूठ और झूठ को सही करने का भी उत्तम व्यापारिक योजनाएं चल रही हैं। जब तक प्रजातंत्र की अभिव्यक्तिओं को प्रसारित एवं संचारित करने से पहले उनका शुद्धीकरण नहीं किया जाएगा, शैक्षिक एकीकरण नहीं किया जाएगा, समान मानवीय विचारधारा के लोगों के निर्माण की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, अपने सांस्कृतिक धरोहर एवं विचार प्रेरकों को सजाया एवं उनका महिमा मण्डन कर प्रसारण नहीं किया जाएगा, जब–तक हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को समझने के लिए अलग से गुरुकुल नहीं बनायेंगे तब–तक सिर्फ द्वेष नहीं वाह्य प्रेरणाओं से भी दुष्कर्म होते ही रहेंगे। सरकार चाहे योगी की हो या सत्ताभोगी की। यह दुष्कर्म घटित होते रहेंगे।

पाश्चात्य प्रभाव एवं सुविधा परस्त जीवनशैली से बढ़ने वाली विकृत मानसिकता के शुद्धिकरण के लिए एवं उत्तम विचारों के सृजन व मानवीय मूल्यों की समझ बढ़ाने के लिए और समाज में संतुलन, न्याय एवं प्रेम का माहौल बढ़ाने के लिए अब आवश्यक हो गया है कि शैक्षिक समानता लागू किया जाए, अभिव्यक्ति की आजादी को फिर से समझा जाए और उस पर नए नियम बनाये जायें। हर साहित्य विचार प्रकाशन व संचारण से पहले उनका भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों एवं मानवीय न्याय की कसौटी पर उन्हें जांचा परखा जाये। उसके बाद लोगों तक उन्हें पहुँचने दिया जाये। वह चाहे महत्वपूर्ण विचार हों या विज्ञापन। खासकर जो अपने निजी या दलगत हित के लिए किसी भी प्रकार की बात या कार्य करने के लिए देखे जाते रहे हैं उनके लिए कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था हो, साथ ही जो लोग द्वेषवश दुष्कर्म करते हैं उन्हें फांसी की सजा से कम सजा ना हो।

समाज हमारे अपने परिवार से भी अहम है क्योंकि परिवार समाज में ही अस्तित्व प्राप्त कर पाता है। अब उस समाज की सुरक्षा व शांति के अनिवार्य प्रश्न पर समझौता करना देश को अस्वीकार्य है। राष्ट्र इस तरह की समस्या का पूर्णरूपेण समाधान चाहता है। पूर्ण विराम चाहता है।

लेखक 'अनिवार्य प्रश्न' समाचार पत्र व 'स्याही प्रकाशन' के प्रकाशक भी हैं।

भ्रष्टतंत्र

# भ्रष्टाचार एक सामाजिक स्वभाव

## भ्रष्टाचार व समाज पर एक बेहतरीन व दार्शनिक शब्द शिल्पांकन पेश कर रहें हैं मुम्बई, महाराष्ट्र के लेखक शंकर केहरी

शंकर केहरी
मुम्बई, महाराष्ट्र

पार्क के कोने वाले झूले पर बैठकर ज्ञानी पांडे सूर्यास्त को निहारने में व्यस्त थे। तभी जिज्ञासु प्रसाद वहाँ पहुँच गए। मित्रवत अभिवादन के बाद जिग्यासु जी ने पांडे जी से पूछा आप इतने ध्यान से ऊपर क्या देख रहे थे?

ज्ञानी पांडे – कुछ खास नहीं, बस यही सोच रहा था कि आखिर डूबता हुआ सूर्य क्या सोचता होगा? दुनिया वाले जिसके प्रकाश के सहारे सब देखते हैं, उसके अस्त को देखकर अनदेखा कर देते हैं और वैकल्पिक रोशनी की चिंता में लग जाते हैं। लोग इसको ही व्यवहारिक होना कहते हैं।

जिज्ञासु – आज आप एकदम दार्शनिक मुद्रा में हैं। मुझे आप से एक खास टॉपिक पर बात करनी थी वह है भ्रष्टाचार। आपको इसकी कोई खास बजह समझ आ रही है?

ज्ञानी पांडे – इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार अब सामाजिक शिष्टाचार बन चुका है।

जिज्ञासु – कुछ समझ मे नहीं आया – भ्रष्टाचार और शिष्टाचार – एक ही साइड में कैसे हो सकते हैं! मुझे थोड़ा और खुलकर बताइए क्योंकि आप कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। लेकिन समझना भी जरूरी है।

ज्ञानी पांडे – देखो भाई, ऐसा है इसके लिए आपको भ्रष्टाचार को समझना होगा। क्योंकि इसका विस्तार बहुत व्यापक और गहन है। इसमे समाज के सभी पहलू समाहित हैं। भ्रष्टाचार अनुपातिक अयोग्यता के ऊपर व्यक्तिगत अपेक्षा की द्विपक्षीय वरीयता का परिणाम है। भ्रष्टाचार का स्वरूप बहुआयामी होता है। इसके उद्गम का मुख्य स्रोत मानव प्रवृति में निहित मैं, मेरा और मेरे का भाव है। यह आदिकाल से चला आ रहा है और अनंतकाल तक चलता रहेगा। धर्म, समाज, राजनीति, प्रशाशन, शिक्षा और व्यवसाय सब मे इसका प्रभाव और प्रचलन है।

जिज्ञासु – आपके अनुसार समाज का कोई भी अंग इससे अछूता नहीं है।

ज्ञानी पांडे – कोई बात नहीं, मैं आपकी दुविधा को अभी दूर कर दूँगा। रोमन चर्च अनुग्रह के बदले राशि लेते थे। इसके विरोध में प्रोटेस्टेंट धारा बनी। आगे चलकर यह विवाद इतना बढ़ा की चर्च को राजसत्ता से अलग करना पड़ा और सेक्युलर शब्द का जन्म हुआ। इस 'सेक्युलर' शब्द ने जितना नुकसान भारत का किया है उतना विश्व के किसी भी देश का नहीं किया है। क्योंकि इस शब्द को संविधान में जोड़ दिया गया लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया। जिसके चलते राजनीति करने वालों ने अपनी सुविधा के अनुसार इसकी व्याख्या की और जनमानस में दुविधा उतपन्न हो गयी। धर्मविहीन व्यक्ति पशु के समान है लेकिन यही बात पंथ विहीन के बारे में नहीं कहा जा सकता है। धर्म का कोई भी पर्यायवाची, समार्थी शब्द अंग्रेजी में नहीं है, रिलिजन तो कतई नहीं। धर्म का सबसे करीबी अर्थ का शब्द क्नजल हो सकता है।

जिज्ञासु प्रसाद – मुझे भारत के संदर्भ में भ्रष्टाचार को समझना है।

ज्ञानी पांडे – खैर, अब बात करते हैं भारत की, विदेशी अक्रांताओं के आगमन से पहले भारत मे भ्रष्टाचार काफी कम था। क्योंकि लोग शास्त्रों में वर्णित नैतिकता से विमुख होने से डरते थे। यह बात जनमानस में थी 'ऊपर जाकर क्या मुँह दिखाऊंगा'। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए राजे रजवाड़ों को प्रलोभन और उपहार देकर अपने लिए अनैतिक और अनुचित सहूलियत लेने लगे। बाद में जब उनका शासन स्थापित हुआ तो वही भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदल गया।

> Hk"Vkpkj eu"; dh LoHkkfod iofRr gS vr% tc rd ekuo lH;rk jgsxh ;g jgk gSvkSj jgsxkA blij vd'k 0;fDxr Lrj dsi;kl lsugh gks ldrk gS lÙkk dsÅijh ik;nku ij cSBk 0;fDr ;fn bekunkj jgk rksbl ij 0;kogkfjd fu;=.k yx ldrk gS

आज की तारीख में केवल आर्थिक भ्रष्टाचार को ही भ्रष्टाचार समझा जाता है। जब पूँजीवाद और साम्यवाद में श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही थी और दोनों के समर्थक विद्वान दोनों विपरीत ध्रूव के समर्थन में अपना तर्क दे रहे थे। पूंजीवाद के आलोचक कहते इस अर्थतंत्र में 'ग्रीड इज गुड' सिद्धान्त भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। दूसरी तरफ साम्यवादी व्यवस्था में शीर्ष पर बैठे लोगों ने आम आदमी के अधिकारों को सीमित कर खुद के लिए धन वैभव एकत्र किया। इस तरह भरष्टाचार पर नियंत्रण करने में दोनों व्यवस्था असफल रही।

कुछ समाज शास्त्री ने कहा कि आर्थिक विकास में सीमित भ्रष्टाचार लुब्रीकेंट का काम करता है। कुछ हद तक यह सत्य भी है। समाज वैज्ञानिक सैम्युएल हटिंगटन का मानना था की भ्रष्टाचार हमेशा नुकसानदेह नहीं होता।

सत्तर के दशक में हिदनहाइमर का यह सिद्धांत काफी लोकप्रिय हुआ था कि जब औद्योगिक विकास होता है और आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं तो लोगों का एक जगह से दूसरे जगह विस्थापन और आवागमन बढ़ता है।

इसमें स्थापित मान्यताएं टूटती हैं और भ्रष्टाचार बढ़ता है। जैसे जैसे मध्यमवर्ग सम्पन्न होता है भ्रष्टाचार कम होने लगता है।

लेकिन यह सिद्धांत भी कालांतर में गलत साबित हुआ। अमेरिका में वाटरगेट कांड और ब्रिटेन का पॉलसन अफेयर इसका उदाहरण है कि संपन्नता से भ्रष्टाचार कम नहीं होता। दूसरी तरफ अविकसित और विकासशील देशों में भी एक से बढ़कर एक घोटाले उजागर हुए उसमें पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों व्यवस्था वाले देश शामिल हैं।

यहाँ तक राष्ट्रवादी मानसिकता रखनेवाले जापान में भी कई प्रधानमंत्रियों को भ्रष्टाचार के चलते अपना पद गवाना पड़ा। भारत में भी घोटालों व घपलों की लंबी फेहरिस्त है, जिसमें बोफोर्स कांड, चारा घोटाला, 2जी घोटाला व कामनवेल्थ घोटाला आदि उल्लेखनीय हैं। जब **IMF** को देशों की विश्वशनियता पर भरोसा नहीं रहा तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था का गठन 1993 में किया गया।

जो देशों का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बनाती है जिसमे 180 देशों को 0–100 के पैमाने पर अंक दिया जाता है। जिसका जितना कम अंक वो उतना भ्रष्ट देश। भारत की स्थिति ब्व्प् में हाल के बरसों में काफी सुधरी है और 85 अंकों के साथ यह चालीसवें स्थान पर है।

जिज्ञासु प्रसाद – आम जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए क्या करना चाहिए और यह कैसे रुकेगा?

ज्ञानी पांडे – भ्रष्टाचार मनुष्य की स्वभाविक प्रवृति है। अतः जब तक मानव सभ्यता रहेगी यह रहा है और रहेगा। इसपर अंकुश व्यक्तिगत स्तर के प्रयास से नहीं हो सकता है। सत्ता के उपरी पायदान पर बैठा व्यक्ति यदि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रहा तो काफी हद तक इस पर व्यावहारिक नियंत्रण लग सकता है।

## कविता

के0 एस0 परिहार
वाराणसी

### जीव कब आनन्द पाया

समझ पाया जिंदगी को,
सुगम जीवन पथ बनाया।
मोह के बंधन में जकड़ा,
जीव कब आनन्द पाया।

छद्म मानक प्रगति के,
हर दम समेटे घूमता है।
प्रेम के रिश्तों को तोड़ा,
धन की गठरी चूमता है।

उम्र के अवसान तक भी,
सत्य पथ न समझ पाया।
मोह के बंधन में जकड़ा,
जीव कब आनन्द पाया।

कल्पनाओं के शहर सब,
भागता है लिये सपने।
वक्त बीता सपन टूटा,
ढूढ़ता फिरता फिर अपने।

था मिला अनमोल जीवन,
व्यर्थ में क्यो कर बिताया।
मोह के बंधन में जकड़ा,
जीव कब आनन्द पाया।

स्फुटित हों भक्ति के स्वर,
प्रीत अंकुर हृदय जागे।
हंस जैसी बुद्धि 'कंचन'
हो जगत के तिमिर भागे।

भ्रम सभी जगबन्ध काटे,
मंत्र जब सद्गुरु से पाया।
मोह के बंधन में जकड़ा,
जीव कब आनन्द पाया।

**कवि राजकीय जिला पुस्तकालय वाराणसी के पुस्तकालयाध्यक्ष हैं !**

सुनिल कुमार सेठ
वाराणसी

### नेता जी की वैकेंसी

पाँच वरष के बाद वैकेन्सी
नेता जी की आयी जी
नगर भ्रमण पर निकल पड़ी हैं
नेता संग परजाई जी

बडी गजब ये वैकेन्सी है
स्वाद चखे जो छोडे ना
हमको ये उपदेश सुनाते
तल लो गरम पकौडे ना
पाँच वरस के पहले वाली
नहीं पटी है खाई जी
नगर भ्रमण पर निकल पड़ी हैं
नेता संग परजाई जी

हाल चाल लेने वाले अब
लोग दिखाई ज्यादा दें
रहे धरातल शून्य परन्तु
ये वादे पर वादा दें
मड़ई भीतर लिट्टी चखते
छोड के दूध मलाई जी
नगर भ्रमण पर निकल पड़ी हैं
नेता संग परजाई जी

जिस चौराहे पर पहले का
गोलम्बर का वादा है
पाँच वरस हैं बीत चुके औ'
गोलम्बर अब भी आधा है
हाथ जुड़े के जुडे रहे हैं
गर्दन रहें नवाई जी
नगर भ्रमण पर निकल पडी हैं
नेता संग परजाई जी

**कवि भेल में कार्यरत हैं !**

## लघुकथा

# पौष की सुबह

मुकेश ऋषि वर्मा
आगरा, उत्तर प्रदेश

पौष की सुबह थी। दो दिन पहले ही भारी कोहरे के बीच भीषण बर्फबारी व ओला वृष्टि हुई थी। परंतु आज सूर्यदेव बादलों के बीच से कभी–कभी दर्शन दे रहे थे। वो अपने खेत की मेड पर बैठा एक टक खेत को देखे जा रहा था।

दो दिन पहले तक खेत हरा–भरा, लहलहा रहा था, लेकिन आज उजड़कर सपाट मैदान हो गया था। उसकी फसल को आवारा गौ एक रात में ही चट कर गईं। वैसे वह रात–दिन खेत पर ही रहकर खेत की रखवाली करता था, पर दो दिन से मौसम जानलेवा हो गया था, इसलिए उसने घर पर रहना ही ठीक समझा।

खेत के उजड़े दृश्य को देखकर उसका हृदय रो रहा था। उसे एक–एक पल याद आने लगा। कैसे उसने महंगा खाद–बीज साहूकार से ब्याज पर पैसे उधार लेकर खरीदे थे। उस समय बाजार में खाद की कालाबाजारी चरम पर थी, इसलिए तिगुनी कीमत पर उसने खाद खरीदा था। हाड़तोड़ ठंड में फसल सींची थी। डीजल महंगा होने से ट्रैक्टर की दोगुनी जुताई भी दी थी। इन विदेशी नस्ल के सांडों और गायों ने उसका सत्यानाश कर दिया।

वो पिछले पांच साल से कभी खेतों पर कटीले तार लगाता है तो कभी झोपड़ी डालकर चौबीसों घंटे वहीं चौकीदार बन कर खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही मौसम अपना रौद्र रूप दिखाता है, तब कुछ समय के लिए उसे मजबूरन खेत छोड़ना पड़ता है और फिर आती है एक दुरूखद संदेश लेकर पौष की सुबह...।

◆◆◆

## लघुकथा

# गौरैया
## एक आत्मकथा

सुबेदार पाण्डेय
वाराणसी, उत्तर प्रदेश

वो मुझे मिली थी सारा शरीर छलनी हो गया था उसका, वह खून से लथपथ हो रही थी, भीषण गर्मी तथा भय से हांफ और कांप रही थी वो, भूख और प्यास से बुरा

हाल था उसका, कौवों का झुंड पड़ा था उसके जान के पीछे किसी तरह बचती बचाती आ गिरी थी मेरी गोद में, उसकी हालत देख मैं अवाक हो ताकता रह गया था, उसे, मेरे हाथों का कोमल स्पर्श पाकर उसे अजीब–सी शांति मिली थी, अपनेपन के एहसास की गहराई से उसका डर दूर हो गया था,वह मुझसे संवाद कर बैठी बोल पड़ी थी , मुझे पहचाना तुमने ,मैं वहीं गौरैया हूं जिसका जन्म तुम्हारे आंगन में हुआ था, मेरी पिढियां तुम्हारे आंगन के कोनों में खेली खाई पली बढ़ी है , वो तुम ही तो हो जो बचपन में मेरे लिए दाना पानी रखा करते थे ,दादी अम्मा के साथ गर्मियों में गंगा स्नान को जाया करते थे, तथा उनके पीछे–पीछे चिंटीयों की बांबी

पर सत्तू छिड़का करते , तुम्हारा घर आंगन मेरे बच्चों की चींचीं चूं चूं से निरंतर गुलजार रहा करता था मेरे रहने का स्थान बंसवारी तथा पेड़ों के झुरमुट और तुम्हारे घर के भीतर बाहर खाली स्थान हुए करते थे,

कितनी संवेदन शीलता थी तुम्हारे समाज के भीतर, कितना ख्याल रखते थे तुम लोग पशुओं पंछियों का, लेकिन अचानक से समय बदला परिस्थितियां बदलीं समय के साथ तुम लोगों के हृदय की दया ममता स्नेह तथा संवेदनाये सब कुछ खत्म होता गया।

अब तो तुम सबका दिल इतना छोटा हो गया उसमें तुम्हारे मां बाप के लिए भी जगह नहीं बची, फिर

हम लोगों का क्या? कौन करेगा हमारा ख्याल ,अरे अब तो अपने स्वार्थ में अंधे बने हमारे रहने की भी जगह छीन ली है तुम लोगों ने,अब न तो हमारे पास भोजन है न तो पानी और ना ही तुम सबकी संवेदनायें ही बची है, अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन हमारी पीढ़ियां प्राणी संग्रहालय में शोभा बढायेगी या फिर किताबों के पन्नों में दफ़न हो कर अपना दम तोड़ती नजर आएंगी, आखिर कब तक तुम लोग साल में एक दिन कभी गौरैया दिवस कभी शिक्षक दिवस कभी मदर्स डे, कभी फादर्स डे मना कर अपने दिल को झूठी तसल्ली देते रहोगे, और फिर अत्यधिक रक्तस्राव के चलते बात करते हुए उसकी गर्दन एक तरफ की ओर झुकती चली गई, और वह सच में मर गई,

उसकी हालत देखते हुए मेरी आंखों से दो बूंदें छलक पड़ी थी,जिनका अस्तित्व उसके उपर गिर कर वातावरण में विलीन हो गया था, और मैं उसका पार्थिव शरीर देख अवाक रह गया था क्यो कि उसने मरते मरतेभी सच का आइना जो दिखा दिया था।

◆◆◆

## अंगार मंथन

# खत्म होती पंचायतों की अहमियत

योगेश कुमार सोनी
लेखक वरिष्ठ पत्रकार है।

समय के साथ सब बदल जाता है, शहर बदला और अब गांव भी बदलने लगे। एक जमाना था कि लोग कानून से भी ज्यादा गांवों की पंचायतों के फैसले पर भरोसा करते व मानते थे। इसके कई कारण होते थे, जैसे कि कानून से फैसला आने में या तो समय लग जाता था या कई बार उतना संतुष्टि भरा फैसला नहीं आता था जितनी उम्मीद की जाती थी। इसके अलावा लोग नहीं चाहते थे कि गांव की बात बाहर जाए चूंकि इससे बदनामी व सम्मान जैसी चीजें भी जुडी होती थी जिसके लिए पंचायत के फैसले को अहमियत दी जाती थी। कुछ समय पहले तक भी गांवों के परिवेश में मामले थाने नहीं जाते थे चूंकि गलत करने वाले को सजा गांव के पंचों द्वारा दे दी जाती थी जिसका आरोपी भी पालन करता था इसके अलावा किसी भी प्रकार के फैसले को टाला नही जाता था।

गांव में जमीनी विवाद,श ादी–ब्याह, पैसों के लेनदेन के अलावा रेप जैसी घटनाओं तक के फैसले हो जाते थे, लेकिन अब, लोग पंचायत के फैसले को अहमियत नहीं देते। इसको लेकर दो चीजें होने लगीं, पहली तो जो बेईमान लोग या यूं कहें कि जिनके मन में चोर होता है वो फैसले से मुकर जाते हैं और दूसरा पंचायतों के फैसले बदलते परिवेश के हिसाब से नहीं होते। मोटे तौर पर समझे तो दोनों पक्षों में से कोई भी संतुष्ट नहीं होता। भारत में कुल गांवों की संख्या 6,28,221 हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 1,07,753 गांव हैं। और हम यदि उत्तर प्रदेश के परिवेश में कुछ घटनाओं के जिक्र के आधार पर ही समझते हैं कि पंचायत के फैसलों की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़के ने लड़की का रेप कर दिया जिस पर पंचायत ने लड़के को पीड़ित लड़की से शादी करने के लिए बोला। जिस पर लड़की के घरवालों समेत सभी राजी भी हो गए। लड़के के परिजन बहुत पूंजीपति थे। उन्होंने लड़की के घरवालों को मोटी रकम देने की पेशकश भी की, लेकिन लड़की नहीं मानी। उसने पुलिस के पास जाने के लिये कहा। लड़की को पूरे गांव ने समझाया व मनाया लेकिन वह किसी की नहीं मानी और उसने पुलिस के पास जाकर मामला दर्ज करवाया। लड़के को सजा हो गयी।

इसके अलावा एक अन्य उदाहरण है– पूरनपुर गांव में रमेश नाम के एक व्यक्ति की जमीन थी और उसको अपनी जमीन जोतने में अपने से आगे वाले की जमीन के मालिक से रास्ता लेना होता था। लेकिन उसने किसी वजह से रास्ता देने से मना कर दिया। पीड़ित ने यह मामला पंचायत को बताया जिस पर उस गांव के अलावा आस–पास के गांव तक के लोग भी आये। उन्होंने जमीन को इस तरह बांट दिया कि दोनों को रास्ता मिल जाए। पंचों ने रमेश से दूसरी जमीन के मालिक को कुछ पैसा भी दिलवा दिया था। चूंकि अब रमेश की जमीन का फ्रंट रोड की तरफ आ गया था। लेकिन कुछ दिन बाद दूसरा पक्ष फैसले से मुकर गया और उसने पीड़ित को रास्ता देने से मना कर दिया। पंचों समेत पूरे गांव ने उसे समझाया लेकिन वह नहीं माना। अंत में पीड़ित को कानूनी सहारा लेना पड़ा और उस पर कानूनी तरह से फैसला होगा। हम इन दो उदाहरणों के आधार पर समझ सकते हैं कि अब दो चीजें हैं। कोई पंचायत की नहीं मानता तो किसी के लिए पंचायत से सही फैसला न मिलने से अहमियत खत्म हो रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारा देश आज गांव प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम लोगों ने इसका महत्व समझना ही खत्म कर दिया। गांव शब्द का अर्थ ठहरावट, धैर्य, विश्वास, सम्मान व अपनेपन का एहसास कराता था, लेकिन इस शब्द का अर्थ बदलती दुनिया में अर्थहीन लगने लगा। गांव के बच्चे शहरों में पढ़ लिखकर अब बड़े होते चले गये और अब वो भी अपनी नयी पीढ़ी को गांव की शैली के विषय में नहीं बताना चाहते।

> **गांव शब्द का अर्थ ठहरावट, धैर्य, विश्वास, सम्मान व अपनेपन का एहसास कराता था, लेकिन इस शब्द का अर्थ बदलती दुनिया में अर्थहीन सा लगने लगा...**
>
> **...बहरहाल, ऐसे तमाम उदाहरण बताने के लिए हैं लेकिन यदि हम पंचायत की हकीकत को समझें तो अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे डाकखाना, लैंडलाइन फोन या अन्य वो चीजें जो बदलते समय के हिसाब से खत्म हो गयीं उनमें पंचायत भी शामिल है।**

बहरहाल, ऐसे तमाम उदाहरण बताने के लिए हैं लेकिन यदि हम पंचायत की हकीकत को समझें तो अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे डाकखाना, लैंडलाइन फोन या अन्य वो चीजें जो बदलते समय के हिसाब से खत्म हो गयीं उनमें पंचायत भी शामिल है। लड़कियों की अपनी मर्जी के पहनावे, लड़का – लड़की की अपनी मर्जी से शादी करने या वो कोई भी कार्य जिससे कोई भी इंसान जो अपनी इच्छा से नहीं कर पाता था अब वह स्वतंत्रता की ओर जा सकता है। चूंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों नजरिये से अब लोग पंचायत के निर्णय से प्रभावित नहीं होते। पहले के लोगों में कुछ समाज और बिरादरी के हिसाब से चलने का बहुत प्रेशर होता था जिस पर लोग मान भी जाते थे लेकिन अब डिजिटल युग में सभी अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं। देशभर में ऐसे तमाम गांव हैं जो केवल नाममात्र के ही गांव रह गये। सडकें व मकान पक्के हो गये जिसके साथ उन लोगों की सोच भी शहरी लोगों जैसी हो गयी।

कुछ जगह देखा जाता है कि लोग अब बाहर या रिश्तेदारों की तो छोड़ो अपने माता – पिता व बड़ों तक की इज्जत नहीं करते। पहले लगता था कि लोग महानगरों में ही ऐसी जिंदगी जीते हैं लेकिन अब गांवों की स्थिति भी वैसी ही है। अब संस्कारों व संस्कृति का शहर गांव से कोई लेना–देना नहीं हैं। यह तो इंसान की परवरिश पर तय करता है।

जिसको इज्जत करनी है वो राह चलते व्यक्ति को भी अपना महसूस कराते हुए उसको सम्मान दे देगा और जिसको नहीं करनी वह अपने माता–पिता की भी नहीं करेगा। बच्चों को प्यार करें और स्वतंत्र जिंदगी जीने का हक व मौका दें लेकिन उन्हें संस्कार व संस्कृति जरूर सिखायें।

बदलना समय की जरूरत है लेकिन उतना बदलो जितने में खुद व दूसरों के साथ प्यार, संस्कार व इज्जत को संभाल सको। अब पंचायत शब्द का अर्थ बदल गया है। बदलते समय के साथ जिसको लोगों ने स्वीकार कर लिया है। वर्तमान में गांवों का हाईटैक होना जारी है। सब लगभग एक समान परिवर्तन के पटल पर बैठे हैं।

◆◆◆

# अब ऑनलाइन मिलेगी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट

**यूपी के तीन जिलों में अलीगढ़, बाराबंकी व मुजफ्फर नगर का किया गया है चयन**

अनिवार्य प्रश्न। संवाद। लखनऊ। प्रदेश में अब से अपनों को खोने के बाद परिवारीजनों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए दर दर भटकना नहीं होगा। इसमें डाक्टरों व कर्मचारियों की लेटलतीफी भी नहीं चल पायेगी। अब पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए उत्तर प्रदेश में एकीकृत सॉफ्टवेयर सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इससे पीड़ित पक्ष ऑनलाइन पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। आगामी मार्च महीने से यह नई व्यवस्था लागू होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ऐसा करने वाला यूपी पहला राज्य होगा।

केंद्र ने राज्यों को 15 अगस्त को पोस्टमार्टम के लिए नया आदेश जारी किया है। इसमें 24 घंटे पोस्टमार्टम की सुविधा शुरू करने के निर्देश है। स्वास्थ्य विभाग ने विगत वर्ष में सभी जिलों के सीएमओ को पत्र जारी कर सूचित कर दिया था। इसमें नए आदेश के तहत पोस्टमार्टम रात में भी करने को कहा गया था।

इसके लिए मेडिको लीगल एक्जामिनेशन एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट व इंटीग्रेटेड लेबोरेटरी रिपोर्टिंग सिस्टम का साफ्टवेयर तैयार होगा। उल्लेखनीय है कि यह चंडीगढ़ के एनआईसी एप्लिकेशन से जुड़ा होगा। इस प्रणाली से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आसानी से अपडेट की जा सकेगी। डॉक्टर, पुलिस, फॉरेंसिक रिपोर्ट सीधे कोर्ट में डिजिटल माध्यम से पहुंचाने के लिए खाका तैयार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को स्वास्थ्य, फॉरेंसिक, पुलिस व फूड एंड ड्रग विभाग को रिपोर्ट अपने यहाँ ऑनलाइन अपडेट करनी होगी। विश्वास जताया जा रहा है कि यह तरीका कोर्ट तक पीड़ितों को समय से न्याय दिलाने में मददगार साबित होगा। वहीं, डॉक्टर व पुलिस को केस से सम्बंधित पूरी रिपोर्ट ऑनलाइन ही अपडेट करनी होगी। एप पर सबंधित केस या घटना का विवरण भी अपडेट करना होगा। इसमें घटना का फोटोग्राफ और वीडियो भी डालने की अनिवार्यता होगी।

# गोकशी बदस्तूर जारी, योगी प्रयास फेल

**उत्तर प्रदेश में गोकशी पर कानून सख्त होने के बाद भी गोकशी करने वालों के हौसले बुलंद, सुस्त पड़े हैं अधिकारी**

घटना में शामिल संदिग्ध एवं प्रयोग की गई चार पहिया वाहन

अनिवार्य प्रश्न। संवाद। आजमगढ़। प्रदेश में गोकशी पर अब पहले से कानून सख्त कर दिया गया है। इसके तहत गोकशी के दोषी को करीब 10 साल की जेल की सजा देने का प्राविधान भी सरकार के प्रयास से किया जा चुका है। फिर भी गोकशी करने वाले कर रहे हैं। गत समय ताजा मामला आजमगढ़ जिला के मुबारकपुर थाने का है। जहां महलिया गांव के निवासी बृजेश पांडे के द्वारा गोकशी करने जा रहे बदमाशों को मना करने पर बदमाशों ने बृजेश पांडे पर ही हमला बोल दिया। पर इकट्ठा हो रहे ग्रामीणों को देखकर गोकशी करने वाले गोवंश को वहीं मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए। घटना के कुछ देर बाद गोकशी करने वालों ने अपने कुछ साथियों की मदद से दोबारा हथियारों के साथ विरोध पर उतारु बृजेश पांडे व अवनीश यादव पर हमला बोल दिया।

सूत्रों के अनुसार बृजेश पांडे व अवनीश यादव द्वारा हल्ला करने पर गांव के काफी लोग जुट गए ऐसे में भीड़ पहुंचने पर गोकशी के प्रयास में लगे बदमाशों के समूह में शामिल करीब 10 लोग भागने लगे। लेकिन उनका एक साथी मौके से ग्रामिणों के हाथ आ गया। एक गाड़ी भी साथ में पकड़ा गई। जिसका नम्बर **UP 65 /AS/ 2400** था।

घटना में ग्रामीणों ने गोवंश चोरी कर रहे एक युवक को दबोच लिया। जबकि उसके कई साथी मौके से फरार हो गए। पकड़े गए युवक को ग्रामीणों द्वारा स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों की तहरीर पर थाना मुबारकपुर की पुलिस ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

ग्रामीणों की मांग है कि गोवंश चोरी करने वालों व उसकी हत्या करने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी लोग धारदार हथियार, बंदूक, हांकी आदि शस्त्र लेकर गांव में चढ़ आये थे उनके ऊपर कार्यवाई होनी चाहिए।

# कानपुर को मिली मेट्रो

अनिवार्य प्रश्न। संवाद। कानपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत समय कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण निर्मित खंड का उद्घाटन किया। यह पूरा 9 किलोमीटर लंबा खंड भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–आई आईटी कानपुर से मोतीझील तक है।

कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है, जिसमें 2 गलियारे हैं, जिनमें से 13 किलोमीटर लंबा रास्ता भूमिगत होगा। इस परियोजना को 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है। पहले मेट्रो गलियारे में 21 मेट्रो स्टेशन और दूसरे गलियारे में 8 मेट्रो स्टेशन होंगे।

कानपुर की वर्तमान जनसंख्या लगभग 51 लाख है, इसके वर्ष 2041 तक 65 लाख तक होने की उम्मीद है। कानपुर शहर में बड़े पैमाने पर विकास होने के कारण शहर में वाहनों की संख्या में भारी विस्तार हुआ है। एक तेज गति से चलने वाली बाधा मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को विकसित और लागू करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के 9 किलोमीटर लंबे खंड का पिछले दिनों उद्घाटन किया गया जिसमें आईआईटी कानपुर और मोती झील के बीच 9 मेट्रो स्टेशन हैं।

परियोजना के पूरी होने का कुल समय 5 वर्ष है और इसके पूर्ण होने की कुल लागत 11076.48 करोड़ रुपए है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में 2 कॉरिडोर शामिल हैं। पहला गलियारा आईआईटी कानपुर से नौबस्ता 23.8 किलो मीटर लंबा है।

जबकि दूसरा गलियारा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्व– विद्यालय से बर्रा 8 तक 8.6 किलोमीटर लंबा है।

# गंगा के निचले हिस्सों में पानी की गुणवत्ता चिंताजनक

**वैज्ञानिकों के एक दल ने पानी की गुणवत्ता में लगातार गिरावट की सूचना दी है**

अनिवार्य प्रश्न। संवाद। नई दिल्ली। वैज्ञानिकों के एक दल ने गंगा नदी के निचले हिस्सों में पानी की गुणवत्ता को खतरनाक स्थिति में पाया है, जिन्होंने उस जगह के जल गुणवत्ता सूचकांक की जरूरी आधार रेखा विकसित की। वैज्ञानिकों के दल ने पानी की गुणवत्ता में लगातार गिरावट की सूचना दी।

मनुष्य के तेजी से बढ़ते दबाव और मानवजनित गतिविधियों के परिणामस्वरूप गंगा नदी में अन्य प्रकार के प्रदूषकों के साथ–साथ नगरपालिका और औद्योगिक सीवेज के अशोधित कचरे को छोड़ दिया जाता है। कोलकाता जैसे महानगर के करीब, विशेष रूप से, गंगा नदी के निचले हिस्से, मानवजनित कारकों, मुख्यतः नदी के दोनों किनारों पर तीव्र जनसंख्या दबाव के कारण बहुत अधिक प्रभावित हैं। नतीजतन, गंगा नदी के निचले हिस्से में नगरपालिका और औद्योगिक सीवेज के अशोधित कचरे के बहने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक अद्वितीय और जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र जैसे सुंदरबन मैनग्रोव और गंगा में रहने वाली लुप्तप्राय करिश्माई प्रजातियों जैसे डॉल्फिन के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है।

प्रदूषण को दर्शाता एक प्रतीक छाया चित्र

आईआईएसईआर कोलकाता में इंटीग्रेटिव टैक्सोनॉमी एंड माइक्रोबियल इकोलॉजी रिसर्च ग्रुप (आईटीएमईआरजी) के प्रोफेसर पुण्यश्लोक भादुड़ी के नेतृत्व में टीम ने गंगा के स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने के लिए जैविक प्रॉक्सी के साथ घुलित नाइट्रोजन के रूपों सहित पर्यावरण के प्रमुख परिवर्ती कारकों की गतिशीलता को समझने के लिए दो वर्षों में गंगा नदी के निचले हिस्सों के 50 किलोमीटर के हिस्से के साथ 59 स्टेशनों को शामिल करते हुए नौ स्थानों की निगरानी की। वैज्ञानिक भार की एक प्रमुख इकाई मीट्रिक से उस जगह का डब्ल्यूक्यूआई लेकर आए हैं, जो गंगा नदी के निचले हिस्से के स्वास्थ्य और पारिस्थितिक परिणामों को समझने में मदद करता है।

उनके अध्ययन से पता चला है कि नदी के इस खंड का डब्ल्यूक्यूआई मूल्य 14–52 के बीच था और नमूने लेने का मौसम होने के बावजूद लगातार बिगड़ रहा था। उन्होंने प्रदूषकों के प्रकार के साथ बिंदु स्रोत की भी पहचान की है, विशेष रूप से नाइट्रोजन के 50 किमी खंड के साथ बायोटा पर प्रभाव के साथ प्रभावी नदी बेसिन प्रबंधन के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष सेंसर और स्वचालन के एकीकरण के साथ–साथ गंगा नदी के निचले हिस्से की दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

◆◆◆

## दी वर्ल्ड जर्नी

# लाजवाब है माटी पर पत्थरों से बना हवा महल

दी वर्ल्ड जर्नी डेस्क

बाडी चौपड़ पर स्थित हवा महल जयपुर के गुलाबी शहर में राजपूतों की शाही विरासत, वास्तकुला और संस्कृति की अद्भुत मिश्रण है। हवा महल को राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक कहा जाता है।

जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया हवा महल एक शानदार इमारत है। इसमें कई झरोखे और खिडकियां होने के कारण इसको "पैलेस ऑफ विंड्स" भी कहा जाता है।

भगवान कृष्ण के मुकुट के जैसी इस इमारत में 953 झरोखें हैं, जो मधुमक्खियों के छत्ते जैसे हैं, ये राजपूतों की समृद्ध विरासत का परिचय देते हैं। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना पांच मंजिला हवा महल सिटी पैलेस के किनारे बना हुआ है। इसकी मुख्य बात यह है कि बिना नींव के बनी यह दुनिया में सिबसे ऊंची इमारत है। हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने सन् 1799 में बनवाया था।

यह महल अब कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग के लिए भी एक बढिया शूटिंग पॉइंट बन गया है। इसमें घूमकर आपको महल का इतिहास, इसकी वास्तुकला और अनेक दिलचस्प तथ्यों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा।

### इसे क्यों कहते हैं हवा महल

इसका अर्थ है हवा का महल। जानकारी है कि इस महल में 953 छोटे–छोटे झरोखे और खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों को महल में ताजी हवा के प्रवेश के लिए बनाया गया था। गर्मी में राहत पाने के लिए महल राजपूतों का खास ठिकाना हुआ करता था, क्योंकि झरोखों में से आने वाली हवा पूरी इमारत को ठंडा रखती थी। लोगों का मानना है कि हवा महल का नाम यहां की पांचवी मंजिल से पड़ा है, जिसे हवा मंदिर कहा जाता है।

### हवा महल का इतिहास

राजस्थान की राजधानी जयपुर है इसमें स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह के पोते ने सन् 1799 में कराया था। कहा जाता है कि वह राजस्थान के झुंझनू शहर में महाराजा भूपाल सिंह द्वारा निर्मित खेतड़ी महल से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस महल का निर्माण कराया। यह रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया गया था। राजस्थान के एक बड़े समाज का मानना रहा है कि ललित जाली की खिड़कियों और पर्दे वाली बालकनी से सजे धजे इस खूबसूरत महल के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य जयपुर की राजपूत महिलाओं को झरोखों में से सड़क पर हो रहे उत्सवों को देखने की अनुमति देना रहा था।

राजस्थानी मानते हैं कि उस वक्त की महिलाएं पर्दा प्रथा का पालन करती थीं और कार्यक्रमों की एक झलक पाने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ पाती थीं। अतः वे अपनी मान्यताओं और मर्यादा को बचाए हुए झरोखों में से उत्सवों का आनंद इसी तरह पूरा ले सकती थीं।

15 मीटर ऊंचाई वाले पांच मंजिला पिरामिडनुमा महल के वास्तुकार लाल चंद उस्ताद थे। 5 मंजिला होने के बावजूद आज भी हवा महल सीधा खड़ा है। यह महल एक ऐसी अनूठी अद्भुत इमारत है, जिसमें मुगल और राजपूत शैली स्थापित है। इमारत का डिजाइन इस्लामिक मुगल वास्तुकला के साथ हिंदू राजपूत वास्तुकला कला का एक उत्कृष्ण मिश्रण को दिखाता है। बताया जाता है कि महाराज सवाई प्रताप सिंह कृष्ण के बड़े भक्त थे, उनकी भक्ति महल के ढांचे के डिजाइन से ही प्रतीत होती है, जो एकदम भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखता है।

महल में 953 नक्काशीदार झरोखे हैं, जिनमें से कुछ तो लकड़ी से बने हैं। इन झरोखों का निर्माण कुछ इस तरह किया गया था कि गर्मियों में ताजी हवा के माध्यम से पूरी इमारत ठंडी रहे।

### दीवारें व आँगन–

आंगन में वर्तमान में एक पुरातत्व संग्रहालय है। महल का आंतरिक भाग भी ऊपर के मंजिल की ओर जाने वाले मार्ग और खंभे से युक्त है। हवा महल के पहले दो मंजिल में आंगन हैं और बाकी तीन मंजिला की चौड़ाई एक कमरे के जितनी बराबर है। खास बात यह है कि इमारत में कोई सीढ़ी नहीं है और ऊपर जाने के लिए रैंप का ही इस्तेमाल किया जाता है। 50 साल बाद 2006 में पूरे हवा महल का रेनोवेशन किया गया। इस समय इस इमारत की कीमत 4568 मिलियन बताई गई थी। उस समय जयपुर के एक कार्पोरेट सेक्टर ने हवा महल के रिनोवेशन का जिम्मा उठाया था, लेकिन फिर बाद में भारत के यूनिट ट्रस्ट ने हवा महल की मरम्मत कराने की जिम्मेदारी ली।

हवा महल की दीवारों पर बने फूल पत्तियों का काम राजपूत शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। साथ ही पत्थरों पर की गई मुगल शैली की नक्काशी मुगल शिल्प का अद्भुत उदाहरण हैं। उत्सवों के लिए पहली मंजिल पर शरद मंदिर बना हुआ है, जबकि हवा महल की दूसरी मंजिल पर रतन मंदिर बना है जिसे ग्लासवर्क से सजाया गया है। अन्य तीन मंजिलों पर विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर है। यहां आपको गुलाबी शहर जयपुर के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। हवा महल का कोई सामने से दरवाजा नहीं है, बल्कि सिटी पैलेस की ओर से एक शाही दरवाजा हवा महल के प्रवेश द्वार की ओर जाता है। यहां तीन दो मंजिला इमारतें तीन तरफ एक बड़े प्रांगण को घेरे हुए हैं, जिसके पूर्वी हिस्से में हवा महल स्थित है।

### कब आएं हवा महल–

सर्दियों के मौसम में भी आप जयपुर हवा महल घूमने आ सकते हैं। नवंबर की शुरूआत से फरवरी के बीच तक का समय यहाँ पर्यटकों का पीक सीजन माना जाता है। हालांकि इस इमारत को निहारने का सबसे सही समय सुबह का है जब सूर्य की सुनहरी किरणें इस शाही इमारत पर पड़ती हैं। ये नजारा हवा महल को और भी सुरूचिपूर्ण और भव्य रूप देता है। लेकिन हवा महल को देखने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित है। हवा महल म्यूजियम शुक्रवार को बंद रहता है, इसलिए बेहतर है कि हवा महल को अन्य दिनों में देखने जाएं।

### कैसे आएं जयपुर के हवा महल–

शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित यह महल अपने संग्रहालय में संरक्षित प्राचीन कलाकृतियों व एक समृद्ध अतीत, सांस्कृतिक विरासत और राजपूतों के शानदार जीवनशैली की झलक को सहेजकर सभी को अपनी ओर खींचता है।

ट्रेन से यहाँ तक पहुंचने के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचना होता है। यहां के लिए ट्रेन हर बड़े और प्रमुख स्टेशनों से मिल जाती है। जयपुर स्टेशन से महल तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी या कैब की भी मदद ले सकते हैं। यहां के स्टेशन से 15 मिनट का समय महल तक जाने में लगता है।

अगर आप सड़क मार्ग से हवा महल पहुंचना चाहते हैं तो जयपुर हमारे देश के सभी हिस्सों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा है। अनेक प्रमुख शहरों से जयपुर के लिए बसें सीधे उपलब्ध हैं।

फ्लाइट से जा रहे लोगों को मुंबई, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता और अन्य शहरों से जयपुर के लिए फ्लाइट सीधी उड़ान में उपलब्ध है। जयपुर के एयरपोर्ट से महल तक जाने में आपको 30 मिनट लग सकते हैं।

# रिमिक्स के बाद अब रिमेक युग

Kajaria
Transform yor world
``गुणवत्ता'' बड़ी चीज है।
SeZ VITRIFIED
संचालक
संतोष गुप्ता
संजय गुप्ता
Showroom of Tiles
Darshn Marble
Baralalpur, Pandeypur, Varanasi, UP
HOUSE OF TILES
Narayanpur, Bhojubir, Varanasi, UP
Help Line- Narayanpur, Bhojubir, 9415620785
Help Line- Pandeypur 8299611409

**आने वाले दशक में बॉलीवुड की अपनी मौलिक विचारधारा की दस बीस ही फिल्में देखने को मिलेंगी, बाकी हजारों की संख्या में साउथ से उधार लिये गए विषयों पर बनी फिल्में देखने को मिलेंगी।**

www.anivaryaprashna.in

मंचदूत डेस्क

मंचदूत डेस्क। मुम्बई–वाराणसी। बॉलीवुड में जैसे कि किसी खास समय में किसी खास मौलिकता को उधार लेने की एक अलग अपनी खुमारी है। बॉलीवुड के म्यूजिक प्रोड्यूसर हमेशा ऐसे रीमिक्स गाने को बनाना पसंद करते रहे जिसके होने की कोई सामाजिक व सांस्कृतिक जरूरत नहीं थी। इन गानों को किसकी मांग पर बनाया गया और क्यों? आम आदमी के बीच इतनी जोर शोर से प्रचलित किया गया जैसे सवाल के जवाब में बॉलीवुड फिल्म जगत का एक भी व्यक्ति सामने कुछ साफ साफ कहने के लिए तैयार नहीं रहता है।

ऐसे ही अब बॉलीवुड से कुछ नई मशहूर फिल्मों को आते देखा जा रहा है। जिनमें अधिकतर फिल्में दक्षिण भारत की बनी हुई लोकप्रिय फिल्मों की मौलिकता और उसकी पटकथा से उठाई गई हैं। बीच में लगातार खराब श्रेणी की फूहड़ फिल्में देने वाला बॉलीवुड शायद यह भाँप गया है कि अब उसके पास मौलिक दिखाने लायक सामग्री तैयार करने लायक लोग नहीं हैं। इसीलिए वहाँ दक्षिण से तमाम फिल्मों को अपने बॉलीवुड के सितारों के साथ बनाया जा रहा है।

जब गानों का रीमिक्स किया जाने लगा था तो पुराने मशहूर और लोकप्रिय गानों को तो लिया ही गया कुछ बेतुके गानों को भी लाकर लोगों के बीच में प्रचलित किया गया। जिसमें हुस्न है सुहानाः कुली नंबर वन, हम्मा हम्माः ओके जानू, एक दो तीनः बागी2, मसकली2: म्यूजिक एल्बम, मुकाबलाः स्ट्रीट डांसर 3डी, दस बहानेः बागी 3, याद पिया की आने लगीः म्यूजिक एल्बम, ओ साकी साकीः बाटला हाउस, छम्मा छम्माः फ्रॉड सईयां व नींद चुराई मेरीः गोलमाल अगेन जैसे हजारों गाने जिसमें कुछ ठीक भी लगे होंगे बाकी सभी बिना सिर पैर के रीमिक्स करके नयी पीढ़ी के लिए बेहद खराब स्तर में संगीत देकर लाया गया।

हालांकि यह थोड़ा सुखद जरूर है कि दक्षिण की कुछ अच्छी फिल्मों को बॉलीवुड ने अपने यहां रीमेक के लिए चुना है। आशा है कि बॉलीवुड की कुछ और आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन चिंता इस बात की है कि क्या बॉलीवुड जैसे विस्तृत फिल्म उद्योग क्षेत्र की अपनी मौलिकता खत्म हो गई है या उनके पास बुरी लतों व फूहड़ कॉसेप्ट के सिवा अब कुछ नहीं बचा। इन दिनों चर्चा है कि साउथ की 20 फिल्मों के रीमेक पर बॉलीवुड का 2022 का फ्यूचर टिका है।

हिंदी फिल्मों के दर्शकों को साउथ की फिल्में डब्ड रूप में तो मिलती ही हैं बॉलीवुड हिंदी फिल्म निर्माताओं द्वारा भी साउथ की फिल्मों को रीमेक करके कई वर्षों से बनाए जाने का चलन आम है। आमीर, सलमान, शाहरुख और दूसरे बड़े अभिनेताओं ने भी साउथ की बनी हुई रीमेक फिल्मों में काम करके ड्रग के शोर में अपने गिरते स्टारडम को बचाया है। जिसमें से वांटेड, कबीर सिंह, गजनी, तेरे नाम जैसी प्रमुख फिल्में शमिल रही हैं।

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि साउथ फिल्मों को हिंदी में बनाने की सबसे बड़ी वजह यह मानी जाती है कि वह अपनी भाषा में बेहद लोकप्रिय होती हैं और उन्हें यूट्यूब एवं अन्य प्लेटफार्म पर खासी व्यूज मिल जाती है। अच्छी दर्शक संख्या वाली फिल्मों को हिंदी में बनाकर हिंदी सितारों के साथ दिखाने से प्रोड्यूशर को नुकसान नहीं होता। इसीलिए अब बॉलीवुड में दिलचस्प कहानियों को खोजकर अधिक दर्शक संख्या वाली फिल्मों को साउथ से लाकर हिन्दी में बनाने का जैसे ट्रेंड चल दिया है। आने वाले दशक में बॉलीवुड की अपनी मौलिक विचारधारा की दस बीस ही फिल्में देखने को मिलेंगी, बाकी हजारों की संख्या में साउथ से उधार लिये गए विषयों पर बनी फिल्में देखने को मिलेंगी।

पिछले साल ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की फिल्म 'लक्ष्मी' को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दर्शकों को शायद ही मालूम हो कि यह फिल्म साउथ इंडस्ट्री की फिल्म 'कंचना' की हिंदी रीमेक थी। भूमि पेडणेकर की फिल्म दुर्गावती तेलुगू तमिल बाइलिंगुअल फिल्म भागमती साल 2019 में रिलीज हुई थी। शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म 'कबीर सिंह' साल 2017 में रिलीज हुई जो साउथ फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' की रिमेक। आयुष्मान खुराना और भूमि पेडणेकर की फिल्म 'शुभ मंगल सावधान' तमिल फिल्म 'कल्याण समयाल साधन' की रीमेक थी। यहां तक कि विद्या बालन और अक्षय कुमार की फिल्म 'भूल भुलैया' 1993 की मलयालम फिल्म 'मणि चित्रा थाजू' से ली गई थी। अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम' 2013 की मलयालम फिल्म 'दृश्यम' की हिंदी रीमेक थी। कई बार फिल्मों का नाम भी साउथ से ले लिया जाता है। हिन्दी सिने संसार के लोगों को अब नाम भी नहीं मिल पा रहा है।

आगे अभी जो साउथ की फिल्में हिंदी में रीमेक होकर आने वाली हैं उनमें प्रमुख रूप से 'जर्सी' मूल फिल्म तेलुगु स्पोर्ट्स ड्रामा 'जर्सी' हिंदी रीमेक धड़क हिंदी मुंबईकर विक्रम बेताल कैथी आदि फिल्में देखने को मिल सकती हैं। यह सारी फिल्में मशहूर साउथ फिल्मों की रीमेक होंगी।

बहरहाल

# फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न

**फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न के विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं वरिष्ठ लेखक**

## सलिल सरोज

लेखक

भारतीय संसद की लोकसभा में कार्यकारी अधिकारी हैं।

जूनियर कलाकारों ने फिल्म के पदानुक्रम के अंत में बहुत कम सौदेबाजी की शक्ति और केवल दैनिक मजदूरी अर्जित करने के साथ 'एक्स्ट्रा' के रूप में उन्होंने भयावह सच का सामना किया है। सवाल यह है कि क्या आप समायोजित करने के लिए तैयार हैं? – क्या एक महिला के रूप में, एक जूनियर कलाकार अवसरों के बदले यौन एहसान प्रदान करने के लिए तैयार है? जैसा कि एक पदानुक्रम पर चढ़ता है। महिलाओं द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति भी बदल जाती है।

फिल्म उद्योग में बड़े पैमाने पर यौन हिंसा ने उस समय सार्वजनिक रूप से ध्यान आकर्षित किया जब एक प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता द्वारा 2017 में अपने सहयोगी महिला कलाकार के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। चलती गाड़ी में उसका अपहरण कर लिया गया था और मारपीट की गई। हमलावरों द्वारा वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। इस मामले में लोकप्रिय अभिनेता –निर्माता, दिलीप को गिरफ्तार किया गया था, और इसने महिला कलेक्टर्स ऑफ सिनेमा कलेक्टिव (डब्ल्यूसीसी) में ऑनलाइन दुर्व्यवहार के सदस्यों को निशाना बनाया, जो पीड़िता के समर्थन में सामने आए थे और उद्योग में कुप्रथाओं पर चर्चा शुरू की थी। दिलीप का मुकदमा पूरा होने वाला है और बचे को फैसले का इंतजार है। यह इस संदर्भ में है कि फिल्म उद्योग में महिलाओं के लिए काम की शर्तों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जो यौन हिंसा और गलतफहमी के माहौल को सक्षम बनाता है।

यूनियनों ने उद्योग की प्रथाओं और मानदंडों को नियंत्रित किया है। हालांकि महिलाओं को इस स्थान पर बड़े पैमाने पर दोषी और अकुशल दिखाया गया है। 'स्क्रीन के पीछे' भूमिका मुख्य रूप से महिलाएँ, पुरुषों द्वारा नियंत्रित की जाती है, जो प्रवेश स्तर पर ही महिलाओं के लिए बाधाएं पैदा करते हैं। यूनियनों ने जानबूझकर महिला कर्मियों की सदस्यता के लिए कुछ स्पष्ट प्रतिबंधों के अलावा प्रक्रिया में देरी की है, उदाहरण के लिए मेकअप कलाकारों जैसे कुछ व्यवसायों में महिला सदस्यता पर सामूहिक प्रतिबंध।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 में महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए अस्तित्व में आया, जो यौन उत्पीड़न से मुक्त कराने के स्पष्ट इरादे से लाया गया था। अधिनियम प्रत्येक कार्यस्थल में दस से अधिक कर्मचारियों की एक समिति के गठन को अनिवार्य करता है, जो यौन उत्पीड़न के किसी भी कथित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए हैं। इस कानून के अनुसार, यौन उत्पीड़न को अवांछित कार्य या व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है जैसे (अ) शारीरिक संपर्क और सीमा उल्लंघन या (आ) यौन एहसान की माँग या अनुरोध (इ) यौन रूप से रंगीन टिप्पणी (ई) कोई पोर्नोग्राफी दिखाना या (अ) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक, गैर–मौखिक आचरण। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न समिति की अनुपस्थिति में, अधिनियम इस अधिनियम के तहत गठित स्थानीय शिकायत समितियों से संपर्क करने के लिए उत्तेजित महिलाओं को भी निर्देशित करता है।

देश भर में, फिल्म उद्योग की संरचना इतनी अनौपचारिक है कि एक कार्यस्थल का गठन खुद अस्पष्ट है। जैसा कि उद्योग के विशेषज्ञ टिप्पणी करते हैं कि काम एक निजी कमरे में हो सकता है जब लोगों का एक समूह एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है, जब एक पोशाक डिजाइनर खरीदारी कर रहा होता है और जब एक जूनियर कलाकार खेल के मैदान में इंतजार कर रहा होता है। भले ही उत्पीड़न विरोधी समिति का गठन कुछ संगठित कार्यक्षेत्रों (उदाहरण के लिए, एक प्रोडक्शन हाउस) में होने की संभावना है, एक कार्यस्थल में किसी व्यक्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई का मतलब ज्यादा नहीं होगा, जो लचीलेपन और कार्य संबंधों की अनौपचारिकता को देखते हुए। अपराधी नियत प्रक्रिया से बच सकते हैं और कहीं भी रोजगार पा सकते हैं। उत्तरजीवी को विभिन्न परियोजनाओं में अपराधी के साथ काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है या अवसर पर छोड़ देने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

अपने स्वभाव से, सिनेमा उत्पादन का भौतिक स्थान निश्चित नहीं है। फिल्म की शूटिंग का स्थान दुनिया में कहीं भी हो सकता है। आंतरिक शिकायत समितियों की अनुपस्थिति में, अधिनियम जिला –आधारित स्थानीय शिकायत समितियों में शिकायत का एक विकल्प प्रदान करता है। सिनेमा के काम की गतिशीलता महिलाओं को इस विकल्प तक पहुँचने से भी रोकती है। जबकि काम मोबाइल है, आंतरिक समितियों का अधिकार क्षेत्र संबंधित जिले तक सीमित है। आदर्श स्थिति में भी, यदि कोई स्थानीय समिति में शिकायत करने का विकल्प चुनता है, तो अधिनियम यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि किसी व्यक्ति को उस स्थान पर शिकायत करनी चाहिए जहां घटना हुई थी या जहां शिकायतकर्ता निवास कर रहा है।

इसके अलावा, अधिनियम कहता है कि नियोक्ता का कर्तव्य है कि वे उन लोगों से सुरक्षा प्रदान करें, जो महिलाएं कार्यस्थल पर संपर्क में आती हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सिनेमा क्षेत्र में कार्यस्थल कोई भी स्थान हो सकता है। एक उद्योग में जहां सितारे करोड़ों की कमाई करते हैं।

गैर–अनुपालन का परिणाम– जैसे कानून द्वारा 50,000 रुपये का जुर्माना अनिवार्य है अगर कोई नियोक्ता एक आंतरिक समिति गठित करने में विफल रहता है एक फिल्म की उत्पादन लागत की तुलना में तुच्छ है। ये हालात और काम की परिस्थितियाँ उद्योग को अधिनियम के साथ डिजाइन द्वारा असंगत बनाते हैं। जुलाई 2017 में, न्यायमूर्ति के. हेमा की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई थी, जिसने डब्ल्यूसीसी से उन शर्तों की जांच करने की मांग की, जो फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न को सक्षम बनाती हैं। डब्ल्यूसीसी ने उद्योग को संचालित करने के लिए प्रणालियों पर सिफारिशें मांगी थीं, इसकी खासियत को देखते हुए। आयोग ने एक लंबी और विस्तृत जांच के बाद दिसंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि, रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। एक आरटीआई द्वारा रिपोर्ट की प्रति मांगने के एवज में इस कारण का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया कि इसमें व्यक्तिगत आख्यान हैं। व्यक्तिगत विवरण को वापस लेने के बाद एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध भी अस्वीकार कर दिया गया था।

एक आपराधिक न्याय प्रणाली जो सबूत के बोझ पर बहुत अधिक निर्भर करती है और जिसे लंबी परीक्षाओं की विशेषता है, महिलाओं को न्याय के लिए बहुत उम्मीद नहीं देती है। खसकर उनको जो यौन उत्पीड़न या हमले का सामना करती हैं। हालांकि, यह एक लोकतांत्रिक राज्य की जिम्मेदारी है कि वह हेमा आयोग की रिपोर्ट को जारी करे और महिलाओं को न्याय देने के लिए एक चर्चा शुरू करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में अपनी सिफारिशें रखे, जिन्हें कम से कम एक ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता है जो न्याय की उम्मीद बढ़ाती है।

**(लेखक भारतीय संसद में कार्यकारी अधिकारी हैं।)**

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक श्री छतिश कुमार द्विवेदी द्वारा यादव प्रिंटर्स, प्रहलाद घाट, वाराणसी, से मुद्रित एवं प्रधान, पंजीकृत व पत्राचार कार्यालय–घोड़सारी, पोस्ट–अमिलिया, शहाबगंज, चकिया, चन्दौली, उ.प्र., पिन : 232118 से प्रकाशित किया गया।
प्रधान संपादक : छतिश कुमार द्विवेदी, RNI No. UPHIN/2019/80493, बाई लाइन समाचारों, विचारों व साक्षात्कारों के लिये प्रकाशक जिम्मेदार नहीं है। सभी विवादों के लिए वाराणसी न्यायालय ही मान्य होगा।
समाचार कार्यालय : 1/253, नारायनपुर, भोजूबीर, वाराणसी–221003 एवं मुंसफ कटरा, जी.टी. रोड, चन्दौली–232304, वेब संपर्क : www.anivaryaprashna.in, ईमेल संपर्क : anivaryaprashna@gmail.com व दूरध्वनि क्रमांक : 9161099088